राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण शनिवार,०८ मई २०२१ वर्ष-४, अंक -१०४ पृष्ठ-०८ मूल्य-०१ रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सर्वे के अनुसार भारत में करीब 30 मिलियन लोग न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित

नई दिल्ली। दिमागी बीमारियों के इलाज में सबसे प्रमुख बात होती है समय से उपचार होना। अकसर इसी वजह से कई मामले बिगड़ जाते हैं। परंतु आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक का अविष्कार किया है जिसके द्वारा दिमागी बीमारियों का समय रहते इलाज किया जा सकेगा। यही नहीं इसके द्वारा इसकी पहचान समय रहते भी हो सकेगी। इस तकनीक के द्वारा नसों के कार्य और मस्तिष्क के रक्त संचार का एक साथ आकलन किया जा सकेगा। इस नई खोज से दिमाग में हुई क्षति और न्यूरो बीमारियों के इलाज में मदद मिल सकती है। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं का कहना है कि नर्व्स की कोशिकाओं (न्यूरॉन्स) और रक्त वाहिकाओं (वॉस्कुलर) जिसे न्यूरोवॉस्कुलर कपलिंग (एनवीसी) कहा जाता है, उनके बीच परस्पर प्रतिक्रियाएं होती हैं। इससे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह नियंत्रित होता है। इस्केमिक स्ट्रोक जैसी बीमारियों का एनवीसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एनवीसी का समय से पता लगने से ऐसी बीमारियों की रोकथाम, निदान और उपचार होता है। सर्वे के अनुसार भारत में करीब 30 मिलियन लोग न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित है। इनमें मिर्गी, स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज, मस्तिष्क आघात और तंत्रिका संक्रमण शामिल है। इस शोध को आईआईटी मंडी के कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. शुभजीत रॉय चौधरी के नेतृत्व में किया गया है। शोध के परिणाम आईईईई जनरल ऑफ ट्रांसलेशन इंजीनियरिंग इन हेल्थ एंड मेडिसिन में प्रकाशित में किया गया है। इसे हाल में अमेरिका का पेटेंट मिल गया है। डॉ. चौधरी ने बताया कि हमारी विधि में मल्टी मॉडल ब्रेन स्टिमुलेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है ताकि न्यूरोवास्कुलर यूनिट (एनवीयू) के विभिन्न कंपोनेंट को अलग-अलग स्टिमुलेट करना है।

10,000 ऑक्सीजन जनरेटर्स, 1 करोड़ मास्क...

कोरोना की दूसरी लहर में संयुक्त राष्ट्र से भारत को बड़ी मदद

नई दिल्ली। भारत को कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में संयुक्त राष्ट्र संघ से बड़ी मदद मिली है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों की ओर से भारत को अब तक 10,000 ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर्स और 1 करोड़ मेडिकल मास्क की सप्लाई की गई है। संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुतारेस के प्रवक्ता की ओर से यह जानकारी दी गई है। यूएन चीफ के प्रवक्ता स्टीफाने दुजारिक ने कहा कि भारत में संयुक्त राष्ट्र की टीम लगातार मदद कर रही है। केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन को लगातार मदद की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण के मामलों का मुकाबला किया जा सके। यूएन चीफ के प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन और यूएन पॉप्युलेशन फंड की ओर से भारत को अब तक 10,000 ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर्स की सप्लाई की गई है। इसके अलावा करीब 1 करोड़ मेडिकल मास्क और 15 लाख फेस शील्ड भी भेज गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की टीम ने भारत की मदद के लिए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स की भी खरीद की है। इसके अलावा यूनिसेफ की ओर से भी

कोरोना से निपटने के लिए जरूरी उपकरणों की सप्लाई भारत को की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बड़ी संख्या में टेस्टिंग मशीनों और किट्स की भी खरीद की है। इसके अलावा एयरपोर्ट थर्मल स्कैनर भी खरीदे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अस्थायी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए टेंट और बेड भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा एजेंसी ने हजारों पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी तैनात किए हैं ताकि कोरोना संक्रमण से निपटा जा सके। यही नहीं यूनिसेफ और यूएन डिवेलपमेंट प्रोग्राम की ओर से भारत में 1,75,000 वैक्सीन सेंटर्स की मॉनिटरिंग में भी मदद की जा रही है। यूनिसेफ के एग्जीक्युटिव डायरेक्टर हेनरिएटा फोरे ने इससे पहले कहा था कि भारत में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने हम सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा था कि इस दौर में पूरी दुनिया को आगे आकर भारत की मदद करनी चाहिए ताकि अन्य देशों में यह न फैले।

भारत में कोरोना से अब तक 2.26 लाख लोगों की मौत

बता दें कि भारत इन दिनों कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से गुजर रहा है। देश में बीते कई दिनों से 4 लाख से ज्यादा कोरोना केस मिल रहे हैं और 3,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना के 2 करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 2,26,000 लोगों की मौत हो चुकी है।

कर्नाटक में 12 मई से आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन

सीएम येदियुरप्पा ने दिए संकेत

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को संकेत दिया कि राज्य भर में लगाए गए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध को 12 मई से आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। येदियुरप्पा ने शुक्रवार सुबह बेंगलुरु के गांधी नगर में एक मंदिर में संवाददाताओं से कहा, हम अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। कठोर कार्रवाई करना अपरिहार्य हो गया है। उन्होंने कहा कि आज और कल की बैठकों में इस पर फैसला हो जाएगा कि किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन की वजह से कर्नाटक में भी इसके विस्तार की संभावना बढ़ गई है।

आज और कल की बैठकों में इस पर फैसला हो जाएगा कि किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन की वजह से कर्नाटक में भी इसके विस्तार की संभावना बढ़ गई है।

कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के 49,058 नए मामले, 328 मरीजों की मौत

कर्नाटक में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 49,058 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 17,90,104 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 328 मरीजों की मौत के बाद प्रदेश में इस संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 17,212 हो गई। बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में ही संक्रमण के 23,706 नए मामले सामने आए जबकि 139 मरीजों ने दम तोड़ दिया। विभाग के मुताबिक, कर्नाटक में 5,17,075 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में आज 18,943 लोग ठीक हुए और अब तक 12,55,797 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में गुरुवार 1,64,441 नमूनों की जांच की गई। अब तक 2.65 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है।

आंध्र प्रदेश-तेलंगाना से दिल्ली आने वालों को 14 दिन रहना होगा क्वारंटाइन

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तीसरी लहर को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक आंध्रप्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने पर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो लोग ट्रेन, बस या हवाई जहाज किसी भी ट्रांसपोर्ट से दिल्ली आएंगे तो उनहें इंस्टीट्यूशनल या पेड क्वारंटाइन करना होगा। 72 घंटे पहले जिनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आई है और जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं, उन्हें सिर्फ सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली होते हुए बिना रुके कहीं और जाने की इजाजत होगी, जो लोग बिना लक्षण वाले हैं और ऑफिशियल काम से दिल्ली आ रहे हैं उनके क्वारंटीन रहना जरूरी नहीं है।

पर्याप्त ऑक्सीजन मिले तो 9500 बेड तैयार होंगे

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि हमने बहुत बड़े स्तर पर योजना बनाई है कि अगर हमें 700 मिट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन मिलती है, तो हम राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 5 हजार बेड बना सकते हैं। हम लोगों ने बुराड़ी अस्पताल में दो जगह 2500 बेड बनाए हुए हैं। कामनवेल्थ गेम्स

विलेज के अंदर एक हजार बेड तैयार किए हैं। यमुना स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के अंदर एक हजार बेड तैयार किए हुए हैं। इस तरह, अगर हमें समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मिले तो, हम 9000 से 9500 बेड तुरंत तैयार कर सकते हैं। अगर 700 मिट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन आने लग गई, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने देंगे।

रायबरेली के सलोन से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री कोरी का कोरोना से निधन

रायबरेली। कोरोना संक्रमण के चलते एक और भाजपा विधायक की इलाज के दौरान मौत हो गई। रायबरेली के सलोन से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री दल बहादुरी कोरी का शुक्रवार को लखनऊ के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले दिनों उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विधायक के निधन की खबर से क्षेत्र में गम का माहौल है। इससे पहले भी कई विधायक और मंत्री की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। यही नहीं कोरोना ने अब तक कई अफसरों को भी छीन लिया है। पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में लगे करीब 700 शिक्षकों की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी खतरनाक लहर में अब तक यूपी विधानसभा के चार सदस्य हमेशा के लिए बिछुड़ गए। पहले रमेश चंद्र दिवाकर, फिर सुरेश श्रीवास्तव, केसर सिंह और अब दल बहादुर कोरी। एक हफ्ते में तीन सदस्य दिवंगत हुए थे। अब तक छह विधायकों की कोरोना से जान जा चुकी है। कोरोना की पहली लहर में पिछले साल दो मंत्री चेतन चौहान व वरुण रानी भी दिवंगत हो गए थे। यूपी की 17वीं विधानसभा में अब तक एक दर्जन विधायकों की मृत्यु हो चुकी है।

पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में लगे करीब 700 शिक्षकों की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी खतरनाक लहर में अब तक यूपी विधानसभा के चार सदस्य हमेशा के लिए बिछुड़ गए।

17 वीं विधानसभा के यह सदस्य हो गए दिवंगत-कमल रानी घाटमपुर(कानपुर शहर), चेतन चौहान नौगाँव सादात (अमरोहा), जगन प्रसाद गर्ग आगरा, जन्मेजय सिंह देवरिया, पारस नाथ यादव मल्हनी(जौनपुर)मथुरा प्रसाद पाल सिकन्दरा (कानपुर देहात),रमेश चन्द्र दिवाकर(औरैया),रामकुमार वर्मा पटेल निघासन(खीरी) लोकेन्द्र सिंह नूरपुर(बिजनौर)वीरेन्द्र सिंह सिरोही (बुलंदशहर) सुरेश कुमार श्रीवास्तव लखनऊ व केसर सिंह बरेली।

रिक्त सीट पर उपचुनाव होना मुश्किल

यूपी विधानसभा में अब 4 सीट रिक्त हैं लेकिन इन पर उपचुनाव करा पाना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में कोरोना संक्रमण अभी काफी बढ़ा हुआ है। चूंकि अगले साल फरवरी में 18वीं विधानसभा के लिए आम चुनाव होना है, जिसमें 9 महीने ही बचे हैं। ऐसे में उपचुनाव के आसार काफी कम ही हैं। वैसे नियमानुसार सीट रिक्त होने के छह महीने में ही चुनाव कराने का नियम है। चुनाव कराने या न कराने का निर्णय चुनाव आयोग को ही करना है।

महाराष्ट्र के वर्धा में शुरू हुआ रेमेडिसिविर का प्रोडक्शन, गडकरी ने अमेरिकी फार्मा कंपनी से कराया था करार

मुंबई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने एंटी वायरल दवा रेमेडिसविर का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। इसे लोगों को सरकार द्वारा तय कीमत पर मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच भारत में रेमेडिसवियर की ब्लैक मार्केटिंग के कई मामले सामने आए हैं। कई शहरों में इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। गडकरी ने कहा, रेमेडिसविर इंजेक्शन की कमी थी। इस वजह से कालाबाजारी की घटनाएं हुईं। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उन्हें रेमेडिसविर नहीं मिला। इसलिए हमने इसका उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, लेकिन हमने कोशिश की (और निर्माण का अधिकार प्राप्त किया), रेमेडीसविर सरकार की कीमत पर लोगों को प्रदान किया जाएगा। अब, मुझे लगता है कि कोई कालाबाजारी नहीं होगी या कोई व्यक्ति इसके अभाव में नहीं मरेगा। स्टॉक अधिक होने पर अन्य राज्यों को भी यह दवाई दी जा सकेगी। गडकरी ने वर्धा में जेनेटिक लाइफ साइंसेज (फार्मेसी) का दौरा कर रेमेडिसविर इंजेक्शन के उत्पादन की देखरेख की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में देश में 35,66,398 सक्रिय मामले हैं।

गुरुवार से शुरू हुआ वर्धा में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन-केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्धा के जेनेटिक लाइफ साइन्सेस के परिसर जाकर उत्पादन का मुआयना किया। अमेरिकी कंपनी गिलायड के पास रेमडेसिविर का पेटंट है, जिसने भारत की सात कंपनियों को लाइसेंस दिया है, जिनमें से एक हेट्रो फार्मा के साथ गडकरी ने वर्धा की जेनेटिक लाइफ साइन्सेस का करार कराया था। इसके तहत हेट्रो फार्मा वर्धा के जेनेटिक के इस परिसर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रेमडेसिविर का उत्पादन कर रही है।

अब स्विट्जरलैंड, पौलेंड, नीदरलैंड और बैंकॉक ने भारत की मदद के लिए बढ़ाए हाथ, भेजी राहत सामग्री

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की जंग में अन्य देशों से भारत को पूरा सहयोग मिल रहा है। संकट की इस घड़ी में भारत के साथ अन्य देश पूरी मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत के लिए ऑक्सजीन संकट सहित मेडिकल उपकरण की कमी को पूरा करने के क्षेत्र में कई देश भारत की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा चुके हैं। यूएस, फ्रांस, ब्राजील और यूके के बाद अब स्विट्जरलैंड, पौलेंड, नीदरलैंड और बैंकॉक भारत की मदद के लिए आगे आया है। इन देशों से भी भारत के लिए विमानों के जरिए राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। तो आइये जानते हैं कि किस देश से भारत के लिए कितनी मात्रा में मेडिकल उपकरण भेजे हैं।

स्विट्जरलैंड ने भेजे कई सौ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 50 श्वसन यंत्र-स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहां से

भारत के लिए भारत कई सौ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 50 श्वसन यंत्र भेजे हैं, जिसकी कीमत CHF 3 मिलियन (लगभग अमरीकी डालर 3.3 मिलियन) है। स्विट्जरलैंड दूतावास ने इसकी जानकारी दी है।

पौलेंड की तरफ से भेजे गई 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खेप

इसके अलावा पौलेंड भी भारत की मदद के लिए सामने आया है। इस देश से महामारी से लड़ने के लिए लगभग 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खेप भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता, अरिंदम बागची ने इस समर्थन के लिए यूरोपीय देश को धन्यवाद कहा है।

नीदरलैंड भी भारत के साथ मजबूती से खड़ा, भेजे मेडिकल उपकरण-उधर, नीदरलैंड भी संकट की इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। यहां से एक फ्लाट के जरिए 449 वेंटिलेटर, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य मेडिकल उपकरण आज भारत में गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, अरिंदम बागची ने कहा कि नीदरलैंड की तरफ अगले कुछ दिनों में बचे हुए मेडिकल उपकरण भारत भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इस मदद के लिए नीदरलैंड का धन्यवाद अदा करते हैं।

बैंकाक की तरफ से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों की मदद-इन देशों के अलावा बैंकाक से भी भारत को मेडिकल उपकरण भेज गए हैं। भारतीय वायु सेना के सी -17 विमान ने बैंकाक से पनागर एयर बेस (पश्चिम बंगाल) तक 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों को एयरलिफ्ट किया है।

टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने की कवायद, प्राइवेट कंपनियों को मिल सकती है वैक्सीन बनाने की अनुमति

नई दिल्ली। केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के निर्माण की अनुमति कुछ और सरकारी तथा निजी कंपनियों को भी देने के विकल्प पर विचार कर सकती है। सूत्रों के अनुसार शीर्ष स्तर पर इस बात पर मंथन चल रहा है और टीकाकरण पर बने वैज्ञानिकों के समूह की राय भी इसके पक्ष में है। केंद्र सरकार को मौजूदा पेटेंट कानूनों के तहत यह अधिकार है कि वह आपात जन स्वास्थ्य की परिस्थितियों के चलते किसी दवा या टीके के निर्माण की अनुमति दूसरी कंपनियों को भी दे सकती है ताकि उसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। 18 साल से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद आने वाले दिनों में टीके की मांग में भारी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। सूत्रों ने कहा कि सरकार टीकाकरण अभियान को तेज करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में सरकार के पास स्वदेशी टीके का तत्काल उत्पादन बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। इसके लिए सरकार कुछ और सरकारी और निजी दवा कंपनियों को अनिवार्य लाइसेंस जारी कर टीका बनाने की अनुमति दे सकती है।

20-25 लाख टीके रोज लगाने का औसत

सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को

कोविशिल्ड की 11 करोड़ और भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की पांच करोड़ डोज के लिए आर्डर दे रखा है जिसकी आपूर्ति अगले मई, जून और जुलाई में होनी है। लेकिन यदि यह आपूर्ति समय पर होती भी है तो इससे तीन महीनों तक मौजूदा रफ्तार से भी टीकाकरण जारी रखना संभव नहीं होगा। जबकि सरकार टीकाकरण तेज करना चाहती है। अभी 20-25 लाख टीके रोज लगाने का औसत है।

तीन सरकारी कंपनियों में उत्पादन का ऐलान हो चुका है

कुछ समय पूर्व सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा के तहत तीन और सरकारी कंपनियों में कोवैक्सीन के उत्पादन का ऐलान किया था। इनमें यूपी स्थित बिबकोल, हैदराबाद स्थित आईआईएल तथा मुंबई स्थित हापकिन बायो फार्मास्युटिकल शामिल हैं। तीनों सरकारी कंपनियां हैं जिनमें उत्पादन शुरू होने में अभी समय लगेगा। कोवैक्सीन को आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर विकसित किया है।

दुनियाभर में पेटेंट प्रावधानों को हटाने की मांग

सरकार कोवैक्सीन के साथ-साथ कोविशिल्ड या भविष्य में देश में बनने वाली किसी अन्य टीके का निर्माण भी इस प्रकिया से करा सकती है। इस बारे में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। यह मांग उठ रही है कि कोरोना के टीकों एवं दवाओं पर से पेटेंट के प्रावधानों को कुछ समय के लिए हटा लिया जाए।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

न्याय का आश्वासन

भारत के लोकतंत्र को लेकर कई शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर किसी संकट की घड़ी में कोई न कोई सांविधानिक संस्था जरूर सहारा बनकर खड़ी हो जाती है। भारत में इस संकट के दौर में पिछले कुछ दिनों से न्यायपालिका की अचानक सक्रियता आश्वस्त करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट जिस तरह कोविड की स्थिति और अन्य सवालों पर भी लगातार आम नागरिकों और सांविधानिक मूल्यों के पक्ष में अन्य संस्थाओं को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ऐसे में, कोई आश्चर्य नहीं कि आए दिन अदालतों की कार्रवाई या उनके फैसले सुर्खियों में बने हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक याचिका पर जो ताजा फैसला सुनाया है, वह भी कई तरह से महत्वपूर्ण है। मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाने के लिए एक याचिका की सुनवाई की थी। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव प्रचार में भारी भीड़ को लेकर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों न हत्या का मुकदमा चलाया जाए। चुनाव आयोग ने इस टिप्पणी को हटाने और मीडिया में इसे छापे जाने पर रोक के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया, लेकिन हाईकोर्ट ने यह आग्रह ठुकरा दिया। तब इस मामले को लेकर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस टिप्पणी को हटाने या मीडिया में इसे छापने पर रोक लगाने से मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और चुनाव आयोग, दोनों ही सांविधानिक संस्थाएं हैं। हाईकोर्ट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तल्ख भाषा न इस्तेमाल की जाए, तो अच्छा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह टिप्पणी चलते-चलते की गई है, इसे फैसले का हिस्सा नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे हटाने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह, मीडिया जब अदालत की कार्रवाई रिपोर्ट करता है, तो वह एक महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है, इसलिए उसे रोका नहीं जाना चाहिए।

आजकल यह प्रवृत्ति कई सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं में देखी जा रही है कि वे अपनी आलोचना के प्रति कुछ ज्यादा संवेदनशील हो रही हैं, अक्सर अपनी आलोचना के खिलाफ या मीडिया में रिपोर्टिंग पर रोक लगवाने के लिए अदालत चली जाती हैं। ऐसी संस्थाओं के लिए इस फैसले में काफी सबक हैं कि अपनी आलोचना के प्रति कैसा रवैया अपनाया जाए। एक तो यह स्वीकार करना जरूरी है कि लोकतंत्र में अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपकी आलोचना होगी, और उससे कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। जैसे कि इस फैसले में कहा गया कि ऐसी टिप्पणियों से या मीडिया में इस बात के छपने से चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता तय नहीं होती। पिछले दिनों चुनाव आयोग की बहुत आलोचना होती रही है और हाईकोर्ट की टिप्पणी भी उसकी ही कड़ी है। हो सकता है, चुनाव आयोग पर लगने वाले सारे आरोप सही नहीं हों, लेकिन आयोग के लिए सिर्फ विश्वसनीय होना ही नहीं, लोगों की नजर में दिखना भी जरूरी है। दुर्योग से चुनाव आयोग काफी हद तक इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। यह पूरा मामला उसे आत्मनिरीक्षण करने के लिए एक मौका देता है।

आरबीआईकी राहत

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड़-19 की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में वित्तीय क्षेत्र को आगे रखने की गरज से व्यक्तियों और सूक्ष्म, लघु एवं उद्यमों को ऋण चुकाने के लिए और समय दिए जाने को मंजूरी दी है। टीका निर्माताओं, अस्पतालों और कोविड़ से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढ़ांचे को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 31 मार्च, 2022 तक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपये तक वित्त पोषण किया जाएगा। इस प्रकार केंद्रीय बैंक जीवन और आजीविका, दोनों की सुरक्षा चाहता है। कोविड़-19 के फैलने पर संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए विश्व के तमाम देशों ने 2020 के शुरुआती महीनों में तालेबंदी को एक उपाय के रूप में लागू किया था। भारत ने भी 'जान है तो जहान है' कहते हुए लॉकड़ाउन लागू किया। बेशकम काफी हद तक यह कारगर रहा लेकिन इससे आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई। तमाम देशों की जीड़ीपी गोता खा गई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। शिथिल पड़तीं आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर भारत ने 'जान भी जहान भी' की बात कहते हुए चरणबद्ध तरीके से लॉकड़ाउन को हटाना शुरू किया। फिर देखा कि भारत की जीड़ीपी की वृद्धि दर में खासी कमी आई। सरकार की यह कहकर आलोचना की गई कि लॉकड़ाउन लगाते समय लोगों के आजीविका के मसले की अनदेखी की गई। पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को सामान्य गतिक्रम में लाने के लिए सरकार को तमाम प्रोत्साहन पैकेज लाने पड़े। बेरोजगार हुए लोगों की क्रयशक्ति घटने या खत्म होने से उपभोग मांग में गिरावट आई और लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाने के लिए एक के बाद एक प्रोत्साहन पैकेज घोषित करने पड़े। अब कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहीं ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है, तो लॉकड़ाउन लगाए जाने की बातें होने लगीं। लेकिन केंद्र में आरूढ़ मोदी सरकार पूर्व अनुभव को देखते हुए पूर्ण लॉकड़ाउन के पक्ष में नहीं है। उसने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि वे चाहें तो रात्रि कर्फ्यू, सप्ताहांत लॉकड़ाउन जैसे उपाय कर सकती हैं। लेकिन पक्की बात है कि इससे आर्थिक गतिविधियों को मंद पड़ेंगी। ऐसे में केंद्रीय बैंक ने उद्यमियों को राहत देने की पहल की है। पहले उपभोक्ताओं के लिएराहत पैकेज थे, अब उद्यमियों पर तवज्जो है। कोशिश है कि अर्थ चक्र बाधित न होने पाए।

परिधि/विशाल तिवारी

'चलता है' पर कब तक?

दूसरी लहर के बीच देश के जिला अस्पतालों से ऐसी कई खबरें आई हैं कि पहली लहर के बाद भेजे गए चिकित्सा उपकरण ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। उनकी पैकिंग तक नहीं खुली हैं। व्यवस्था की अकर्मण्यता का यह नग्न प्रदर्शन है। यह अकर्मण्यता जरा भी आश्चर्यचकित नहीं करती। देश की मानसिकता में व्याप्त लालफीताशाही की जड़ता महामारी में भी नहीं टूटी। इसकी बानगी दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी में भी मिलती है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि विदेशों से सहायता के रूप में आने वाले चिकित्सा उपकरण लोगों की मदद के लिए हैं और इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये बक्से में बंद ना रह जाएं। बता दें कि विश्व के कई देश भारत की मदद को आगे आए हैं। इसके तहत ऑक्सीजन सिलेंडरग ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, वेंटिलेटर्स इन देशों द्वारा भेजे गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कस्टम से ऐसे उपकरणों को जल्द क्लीयरेंस मिलनी चाहिए। इस महामारी में भी कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है, यह शर्मनाक है। यह बताने के लिए काफी है कि हमारी व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इस अप्रत्याशित समय में भी 'चलता है' का रवैया अपनाए हुए है। जबकि आदर्श स्थिति तो यह होती कि कोरोना उपचार से संबंधित किसी भी प्रकार के उपकरण व दवाइयों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए, बिना समय गंवाए इन्हें जरूरत के हिसाब से देश में जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। इनके आयात से संबंधित सभी प्रकार के टैक्सों को फिलहाल निष्प्रभावी कर देना चाहिए। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारी व्यवस्था का एक हिस्सा है 'चलता है' से बाहर नहीं निकल पाया। वो आज भी बरसों पुरानी मंथर गति से सक्रिय है। आज जब हर तरफ युद्ध स्तर पर सक्रियता समय की मांग है, त्वरित समन्वय से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। जड़ता की यह स्मस्या सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अमूमन जो सहायता नंबर जारी किए जाते हैं, उनमें कई काम नहीं करते। इस प्रकार की तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-बड़ी खामियां इस दौरान उभरकर आई हैं। अगर यह दुरुस्त रहती तो कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। अभी भी जो संभव हो किया जाए। केंद्र-राज्य सहकारी संघवाद की विचारधारा के तहत काम करते हुए, जहां जिसको जितनी जरूरत हो उस हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल करें। रस्मी कार्रवाइयों से जितना बचेंगे, उतनी ही जिंदगियों को हम बचाने में कामयाब हो पाएंगे।

ताकि दुनिया में सबको मिले टीका

अरविंद गुप्ता

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अमेरिका ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के उस प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है, जिसमें इन दोनों देशों ने 'ट्रिप्स' समझौते के कुछ प्रावधानों में छूट देने की बात कही थी। ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा तय एक बहु-राष्ट्रीय समझौता है, जिस पर 1 जनवरी, 1995 को हस्ताक्षर किया गया था। इसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा के न्यूनतम मानक तय किए गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका पिछले साल अक्तूबर से ही बढ़-चढ़कर मांग कर रहे हैं कि कोरोना टीके या इसकी दवाइयों को लेकर बौद्धिक संपदा के अधिकारों को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए, ताकि क्षमतावान देश कोरोना के टीके और दवाइयां बना सकें। इससे न सिर्फ दुनिया के हरेक जरूरतमंद देश तक दवाइयां व टीके पहुंच सकेंगे, बल्कि कोरोना महामारी से बड़े पैमाने पर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत और दक्षिण अफ्रीका के इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है, यह तो अगले महीने होने वाली इसकी बैठक में ही पता चल सकेगा, मगर इसमें अमेरिका का समर्थन काफी मायने रखता है। उल्लेखनीय है कि दवा-निर्माण के क्षेत्र से जुड़ी ऐसी कई अमेरिकी कंपनियां हैं, जो कच्चा माल, तकनीक आदि उपलब्ध कराती हैं। अमेरिकी सरकार के फैसले का भले ही वहां की कुछ दवा कंपनियों ने विरोध किया है, लेकिन डब्ल्यूटीओ की बैठक में सदस्य देशों की सरकारें फैसला लेती हैं, कंपनियां नहीं। हालांकि, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका के राजी होने मात्र से पेटेंट में छूट संबंधी भारत व दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ से पारित हो जाएंगे। इसकी बैठक में सर्वसम्मति से फैसला होता है और यूरोपीय देशों की कई कंपनियां इस प्रस्ताव के विरोध में हैं। इसलिए यह देखने वाली बात होगी कि वे अपनी-अपनी सरकारों पर कितना दबाव बना पाती हैं, या फिर वहां की सरकारें अपनी-अपनी दवा कंपनियों के दबाव को कितना नजरंदाज कर पाती हैं? वैसे, इस प्रस्ताव का पारित होना मानवता का तकाजा है। अभी पूरी दुनिया कोविड-19 की जंग लड़ रही है। 32 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। बेशक, कई देशों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन करीब 120 राष्ट्र अब भी ऐसे हैं, जहां कोरोना टीके की एक भी खुराक नहीं पहुंच सकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि गिनी-चुनी कंपनियों के पास ही पेटेंट अधिकार हैं और वही टीके का उत्पादन कर रही हैं। चूंकि इन कंपनियों की क्षमता भी सीमित है और इनसे उत्पाद लेने की प्रक्रिया लंबी व जटिल, इसलिए खरीदार देशों तक टीके पहुंचने में भी वक्त लग रहा है। फिर कई देश महंगी कीमत होने के वजह से इन कंपनियों की मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। लिहाजा, विश्व व्यापार संगठन यदि भारत और दक्षिण अफ्रीका के सुझाव को मान लेता है, तो भारत जैसे कई देशों में वैक्सीन निर्माण-क्षमता का विस्तार होगा और जरूरतमंदों तक टीके पहुंचाए जा सकेंगे। टीकाकरण अभियान को खासा गति मिल सकेगी। इस छूट के आलोचक तर्क दे रहे हैं कि यदि इस प्रस्ताव को मान लिया गया, तो दवा अथवा टीके के शोध और अनुसंधान पर असर पड़ेगा। आपूर्ति श्रृंखला के कमजोर होने और नकली वैक्सीन या दवा को मान्यता मिलने की आशंका भी वे जता रहे हैं। मगर इसमें पूंजी का खेल भी निहित है। चूंकि ट्रिप्स समझौते के तहत कंपनियां सूचना व तकनीक साझा करने से बचती हैं, इसलिए उनका लाभ बना रहता है। पेटेंट में छूट मिल जाने के बाद उन्हें अपना लाभ भी साझा करना पड़ेगा, जिस कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। मगर विरोधियों को वह दौर याद करना चाहिए, जब विशेषकर अफ्रीका में एड्स का प्रसार अप्रत्याशित रूप से दिखा था। उस समय एड्स की 'ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी' 10,000 डॉलर सालाना प्रति मरीज की दर से विकसित देशों में संभव थी, मगर अब एक भारतीय जेनेरिक कंपनी इसे महज 200 डॉलर में बना रही है। स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसा ही प्रयोग ब्राजील, थाइलैंड जैसे देशों में भी हुआ है। यह इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि दवा-निर्माण में पेटेंट संबंधी छूट मिली। नतीजतन, व्यापक पैमाने पर एड्स की दवाइयां बननी शुरू हुईं और यह महामारी नियंत्रण में आ गई। आज भी यही किए जाने की जरूरत है। ऐसे वक्त में, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं और बड़े देशों को यह सोचना होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था बने, जिसमें सभी राष्ट्रों को दवाइयां मिलें, टीके मिलें और कोविड-19 की जंग वे सफलतापूर्वक लड़ सकें। अगर किसी भी एक देश में कोरोना का संक्रमण बना रहता है, तो खतरा पूरे विश्व पर कायम रहेगा। इसलिए इस काम में अमीरी और गरीबी का भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि विकसित राष्ट्र अपने नागरिको को कोरोना से बचा ले जाने का सपना देखें, और गरीब देश वायरस की कीमत चुकाते रहें।

> यहां एक व्यवस्था यह हो सकती है कि जब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बाबत कोई ठोस फैसला नहीं ले लेता, तब तक कंपनियां आपस में करार करके कोरोना टीका अथवा दवा-निर्माण के कार्य को तेज गति दें।

यहां एक व्यवस्था यह हो सकती है कि जब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बाबत कोई ठोस फैसला नहीं ले लेता, तब तक कंपनियां आपस में करार करके कोरोना टीका अथवा दवा-निर्माण के कार्य को तेज गति दें। इसमें यह संभावना बनी रहती है कि कंपनियां सूचना, शोध, अनुसंधान अथवा तकनीक आपस में साझा करती हैं। मगर यह आपसी विश्वास का मामला है। अगर कंपनियों को आपस में भरोसा है और लाभ कमाने की अपनी मानसिकता को वे कुछ वक्त के लिए टालना चाहती हैं, तो वे आपस में हाथ मिला सकती हैं। यह विशुद्ध रूप से कंपनियों के बीच का करार होता है और इसमें सरकारों की कोई दखलंदाजी नहीं होती। मगर आमतौर पर कंपनियां ऐसा शायद ही करना चाहेंगी। बिना फायदे के आखिर वे क्यों काम करेंगी?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

चर्चित चेहरा

विजयन के विजय मंत्र से खुले जंतर

भले की पश्चिम बंगाल के राजनीतिक प्रलाप में केरल की क्रांति की अनुगूंज दूर तक न सुनी गई हो लेकिन केरल के खेवनहार पिनराई विजयन ने कमाल किया है। उन्होंने चालीस साल की उस परंपरा को तोड़ा है, जिसमें जनता केरल में हर पांच साल में दूसरे राजनीतिक समूह को सत्ता सौंप देती थी। राजनीतिक सत्ता को जो बंटवारा एलडीएफ व यूडीएफ में होता था, उसे विजयन ने रोक दिया है। विजयन के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। कहा जाता है कि सत्ता के खिलाफ जनता में पांच साल बाद मोहभंग की स्थिति होती है, लेकिन पिछले चुनाव में जहां 140 सदस्यों वाले सदन में उसे 91 सीटें मिली थी, वहीं इस बार 93 सीटें मिली हैं। चुनाव में न कोई स्टार प्रचारक थे और न ही केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा हस्तक्षेप। वे अकेले पार्टी के खेवनहार बने रहे। दरअसल, पिछले पांच साल में कार्यों के जरिये जनता में विजयन यह विश्वास जगाने में सफल रहे कि अगर कोई मुसीबत आएगी तो वे मजबूत नेतृत्व दे पायेंगे। वे आपदा प्रबंधक के रूप में उभरकर सामने आये हैं।

सबसे बड़ा कमाल जो विजयन ने किया, वह था अल्पसंख्यक वोटों को एलडीएफ में लाने का, जो अब तक यूडीएफ का आधार हुआ करता था। ऐसा इसलिए कि सीपीएम को हिंदुओं की पार्टी माना जाता था और मुस्लिम व ईसाई मत यूडीएफ की झोली में चले जाते थे। यूडीएफ में उनके टक्कर का कोई नेता न होने का लाभ भी एलडीएफ को मिला। उन्हें पता था कि जनता को क्या संदेश देना है, जबकि यूडीएफ गफलत में रहा।

दरअसल, विजयन ने चुनाव में गोटियां खुद बैठायीं। उन्होंने खुद प्रत्याशियों का चुनाव किया। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों को अपनी राजनीति में तरजीह दी। उन प्रत्याशियों का पत्ता काटा जो दो बार चुनाव जीत चुके थे। इसके चलते नये उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिला। उनका यह फार्मूला पार्टी के लिये कामयाबी का साधन बना। दूसरे विजयन की छवि राज्य में एक ईमानदार नेता की रही। जो भी विवाद राज्य में पिछली सरकार के दौरान हुए उनमें विजयन का नाम नहीं उछला। इसके इतर लोक कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा आपदा प्रबंधन की कुशलता ने लोगों का दिल जीता। खासकर कोविड-19 की महामारी में उनकी सरकार ने बेहतर ढंग से काम किया।

इस राज्य में देश का पहला कोविड संक्रमित व्यक्ति मिला था, लेकिन राज्य ने सुनियोजित ढंग से इसका मुकाबला किया। राज्य सरकार के कोविड नियंत्रण प्रयासों की विश्व स्तर पर भी प्रशंसा हुई। महामारी के दौरान उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई। राशन देने में अभिनव प्रयोग से लोगों को लाभ हुआ। जिसके चलते आपदा में लोगों के पास अनाज के साथ पैसा भी था। पेंशन व राशन किट योजना के साथ ही एक भरोसा लोगों में था कि उनका नेतृत्व उनकी मुसीबत में संवेदनशील रहता है। यही वजह है कि दूसरी बार सत्ता में आने के लिये चुनाव लड़ने वाले दलों के खिलाफ पैदा सत्ता-विरोधी भावना नजर नहीं आई।

दरअसल, जनता में एक भरोसा कायम हुआ कि राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो हमारा नेतृत्व उससे जूझने में सक्षम है। राज्य में दो बार बाढ़ आई, निपाह वायरस संकट व कोरोना महामारी में सक्रियता से सरकार में जनता का भरोसा बढ़ा। सरकार की धरातल पर उतरी योजनाओं का ही नतीजा है कि जब पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन के चलते हाहाकार मचा है तो केरल कई राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। अभी राज्य ने पूरी क्षमता से काम करना शुरू नहीं किया है।

एक बड़ा दांव विजयन ने पार्टी के जनाधार को बढ़ाकर यूडीएफ का आधार खिसकाने के लिये चला। उन्होंने मुस्लिम वोटों को पार्टी की तरफ मोड़ा जो यूडीएफ में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाताओं में यह सोच विकसित हुई कि भाजपा के उदय में उनका हित नहीं है। यह भी कि एलडीएफ के साथ जाने में ही उनके हित सुरक्षित रह सकते हैं। इतना ही नहीं, वे पार्टी के पक्ष में ईसाई मतों का ध्रुवीकरण करने में भी सफल रहे। कांग्रेस की मददगार रही केरल कांग्रेस को वे एलडीएफ के साथ लाने में कामयाब रहे, जिससे ईसाई मत एलडीएफ को मिले। बताया जाता है कि राज्य में सत्ताइस प्रतिशत मुस्लिम व सत्रह प्रतिशत वाले ईसाई समुदाय से जरूरी वोट पार्टी के लिये निकालने में सफल रहे।

सख्त मिजाज वाले पिनराई विजयन को केरल में 'धोती पहनने वाला मोदी' भी कहते हैं। कुछ लोग उनकी तुलना रूस में साम्यवादी नेतृत्व करने वाले स्टालिन से करते हैं। विजयन एक मजबूत व कर्मठ राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल, मोदी की तरह ही विजयन भी साधारण परिवार से आते हैं। कन्नूर जिले के पिनराई गांव के रहने वाले विजयन के माता-पिता ताड़ी बनाने वाले एल्वा समुदाय से आते हैं। उनके नेतृत्व में मोदी जैसी खूबियां लोग देखते हैं। छात्र जीवन में वाम राजनीति में आये विजयन ने अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की थी। इमरजेंसी के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उन पर अत्याचार भी किये थे। भारतीय युवा परिसंघ में सक्रिय रहने के बाद 1998 में वे सीपीएम के राज्य सचिव बने और यह पद लगातार सत्रह वर्ष तक संभाला। उन पर निरंकुश व्यवहार का भी आरोप लगा। वे सुनते सब की रहे लेकिन फैसला खुद लेते हैं। यही वजह है कि उनकी तुलना स्टालिन से भी की जाती रही है। आज वे पार्टी में एकछत्र राज करने वाले नेता हैं।

आईपीएल

बाहर ले जाने की कवायद

मनोज चतुर्वेदी

देश में आजकल कोरोना की वजह से बिगड़े हालात में आईपीएल के आयोजन का थोड़ा विरोध हो रहा था लेकिन आयोजक इस विरोध को दरकिनार करके आयोजन को जारी रखे हुए थे। लेकिन कोरोना ने टी-20 लीग के बॉयो बबल में सेंध मारकर आयोजकों को इसे स्थगित करने को मजबूर कर दिया। सही है कि आयोजन की योजना बनाते समय देश के हालात इतने खराब नहीं थे। लेकिन देश में कोरोना के प्रकोप से हाहाकार की स्थिति बन जाने पर भी आयोजकों का मैचों को जारी रखना थोड़ा खलने वाला जरूर था। पर अब इसके स्थगित हो जाने पर मैचों को विदेश ले जाने की कवायद शुरू हो गई है।

आईपीएल आयोजकों ने विभिन्न टीमों में कोरोना के केस आने पर भी लीग को बचाने का प्रयास किया था। केकेआर और आरसीबी के मैच से पहले केकेआर के दो खिलाड़ियों वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर के कोरोना पॉजिटिव आने पर कुछ आयोजक इन दोनों को आइसोलेट करके इनके चोटिल होने की वजह से नहीं खेलने की बात कहकर मुकाबले को जारी रखना चाहते थे। लेकिन आरसीबी प्रबंधन के खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए खेलने से इंकार करने और अगले ही दिन सनराइजर्स हैदराबाद के ऋद्धिमन साहा के पॉजिटिव आ जाने से स्थिति हाथ से निकल गई। इस स्थिति में भी जब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और फ्रेंचाइजियों की आपात बैठक हुई तो काफी लोग लीग जारी रखने के पक्षधर थे। लेकिन कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस के आकाश अंबानी, दिल्ली कैपिटल्स के पार्थ जिंदल और आरसीबी प्रबंधन के अड़ जाने पर इसे स्थगित करना पड़ा।

सवाल है कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए इस लीग को रद्द भी किया जा सकता था पर स्थगित किया गया। इसकी वजह इस टी-20 लीग में भारी रकम का दांव पर लगे होना है। रद्द कर दिया जाता तो बीसीसीआई को 2000 करोड़ रुपये की रकम ही मिलतीग जबकि पूरा आयोजन होने पर 4000 करोड़ से ज्यादा रकम मिलने की उम्मीद थी। आईपीएल के महद्मव को इस तरह भी समझा जा सकता है कि विश्व क्रिकेट की आर्थिकी करीब 15000 करोड़ की है, जिसमें से 5000 करोड़ रुपये सिर्फ आईपीएल से आते हैं।

बीसीसीआई के सामने विचारणीय प्रश्न है कि लीग के बाकी 31 मैचों को किस तरह और कहां आयोजित किया जाए। भारत की मौजूदा हालत को देखते हुए और कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा से साफ है कि इन मैचों का अब भारत में आयोजन शायद ही हो। कहा जा रहा है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और फ्रेंचाइजी टीमें बाकी मैचों को विदेश ले जाने को सहमत हैं। पहला विकल्प बाकी मैचों को संयुक्त अरब अमीरात ले जाने का है। पर इसमें दिक्कत है कि संयुक्त अरब अमीरात सितम्बर में बेहद गर्म होता है और इस मौसम में खिलाड़ियों खासकर विदेशी खिलाड़ियों को दिककत हो सकती है। दूसरा विकल्प इंग्लैंड़ है। सितम्बर माह में इंग्लैंड़ का मौसम सुहाना होता है जो कि आयोजन के लिए बेहद माफिक रहेगा। इंग्लैंड़ आने में किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी पर बीसीसीआई को आईपीएल के बाकी मैच कराने के अलावा अक्टूबर में टी-20 विश्व कप के आयोजन पर भी विचार करना है। मौजूदा हालत को देखकर तो टी-20 विश्व कप का आयोजन भी आसान नजर नहीं आता।

पहले बीसीसीआई ने सोचा था कि प्रस्तावित नौ शहरों के बजाय पांच शहरों में ही मैचों को सीमित किया जाए पर मौजूदा हालात में पांच शहर भी मैच कराने की स्थिति में नहीं लग रहे। वैसे इस आयोजन में पांच माह बाकी हैं और इस दौरान स्थिति सामान्य भी हो सकती है। आईसीसी ने इसके वैकल्पिक आयोजन स्थल के तौर यूएई का चयन किया है। अगर यूएई में विश्व कप होता है तो उससे पहले आईपीएल के मैच कराना शायद ही संभव हो। इसलिए यह भी सोचा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया के हालात सामान्य हो जाते हैं तो इस साल टी-20 विश्व कप का ऑस्ट्रेलिया आयोजन कर ले और भारत में 2022 के टी-20 विश्व कप का आयोजन हो जाए। अभी तो बीसीसीआई विदेशी खिलाड़ियों को सुरक्षित घर भेजने में जुटी हुई है। लेकिन जल्द ही आईपीएल के बाकी मैचों को विदेश ले जाने की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। इन बातों से यह तो साफ है कि जरा भी उम्मीद रहने पर बीसीसीआई आईपीएल पूरी करने से पीछे हटने वाली नहीं है क्योंकि उसकी बड़ी राशि दांव पर लगी हुई है।

मजबूत वैश्विक रुख से सोने में 474 रुपये और चांदी में 1,050 रुपये का सुधार

नयी दिल्ली, वैश्विक बहुमूल्य धातुओं में मजबूत लिवाली के बीच स्थानीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 474 रुपये की तेजी के साथ 47,185 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्युरिटीज ने यह जानकारी दी है। इससे पहले के कारोबारी सत्र में सोना 46,711 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,050 रुपये की तेजी के साथ 70,791 रुपये प्रति किलो ग्राम हो गयी। पिछले सत्र में यह 69,741 रुपये पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्यूरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ''वैश्विक सोने की कीमतों में तेजी आने के साथ दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 474 रुपये की मजबूती आई।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,820 डालर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 27.33 डालर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रहा ।

डेलमोस एविऐशन रूस से राजस्थान के लिये 100 आक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स की पहली खेप लाई

मुंबई, रुस की विमानन कंपनी एयरोफ्लोट के लिये सामान्य बिक्री एजेंट का काम करने वाली कंपनी डेलमोस एवियेशन रूस से 100 आक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स नयी दिल्ली लेकर आई है। इन्हें राजस्थान सरकार के लिये लाया गया है। कंपनी ने कहा है कि उसने राजस्थान मेडिकल सविर्सिज कार्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) के साथ इस काम के लिये गठबंधन किया है। कंपनी रूस से 1,250 आक्सीजन कंस्ट्रेटर्स की खरीद करेगी, उनका परिवहन और उन्हें सुपुर्द करने का काम कंपनी को दिया गया है। डेलमोस एवियेशन ने कहा है कि 100 कंसन्ट्रेटर्स के साथ पहली खेप को एयरोफ्लोट एयरबस ए333 से उड़ान संख्या एसयू 232 के जरिये प्रातः नौ बजे के करीब नयी दिल्ली पहुंचा दिया गया है।कंपनी ने कहा है कि हवाईअड्डे से इस चिकित्सा सामग्री को सड़क मार्ग से जुयपुर आरएमएससीएल के मुख्यालय तक पहुंचाया जायेगा। शेष 1,150 आक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स को तीन खेपों में नयी दिल्ली लाया जायेगा। ये खेप क्रमशः नौ, 14 और 16 मई को नयी दिलली पहुंचेगी।

सैमसंग ने बिक्सबी अपडेट के साथ भारतीय अंग्रेजी सपोर्ट शुरू किया

नई दिल्ली। भारतीय यूजर्स के लिए इसे और अधिक अनुकूल बनाने के लिए, दक्षिण कोरियाई तकनीकी दिग्गज सैमसंग ने शुक्रवार को बिक्सबी 3.0 अपडेट के हिस्से के रूप में भारतीय अंग्रेजी (इंडियन इंग्लिश) को जोड़ने की घोषणा की। बिक्सबी अन्य लोगों के बीच भारतीय नामों, स्थानों, संबंधों, सामग्री और व्यंजनों को समझ सकता है। यह यूजर्स को दिन भर में कई चीजों की सहायता भी कर सकता है। सैमसंग आर एंड डी बेंगलुरू में वॉयस इंटेलिजेंस टीम के सीनियर डायरेक्टर और प्रमुख गिरिधर जक्की ने एक बयान में कहा, नवीनतम अपडेट, जो बिक्सबी 3.0 में भारतीय अंग्रेजी के लिए सपोर्ट लेकर आया है, वह हमें इस दिशा में एक कदम और करीब ले जाता है। उन्होंने कहा, हमारी विभिन्न टीमों ने बेंगलुरू, दिल्ली और नोएडा में आर एंड डी (अनुसंधान एवं विकास) केंद्रों में यह सुनिश्चित किया कि हम भारत में बोली जाने वाली अंग्रेजी के कई फ्लेवर्स को कवर कर सकें। बिक्सबी के नए संस्करण का उद्देश्य नए और बेहतर भारतीय अंग्रेजी अवतार के माध्यम से दैनिक परिदृश्यों को नियंत्रित करना है। कंपनी ने कहा कि 2017 में अपनी शुरूआत के बाद से, बिक्सबी एक खुले, स्केलेबल एआई प्लेटफॉर्म के लिए यूजर्स के लिए एक एंटेलिजेंट वॉयस असिस्टेंट से विकसित हुआ है, जो कभी भी मोबाइल डिवाइस, वियरेबल्स और डिजिटल डिवाइस में कहीं भी उपलब्ध है। उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाने और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बिक्सबी सुविधाओं को और अधिक सार्थक और प्रासंगिक बनाने के लिए, सैमसंग ने बिक्सबी 3.0 के हिस्से के रूप में भारतीय अंग्रेजी के लिए सपोर्ट पेश किया है।

रिजव बैंक ने बैंकों से कहा कि रिण मिलने के 30 दिन के भीतर स्वास्थ्य कंपनियों को आगे कर्ज दें

मुंबई,

रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन्हें विशेष तौर पर घोषित 50,000 करोड़ रुपये के नकद धन की सुविधा का के तहत मिलने के बाद 30 दिन के भीतर उससे स्वास्थ्य सेवायें देने वाली कंपनियों को कर्ज उपलब्ध कराना होगा। रिजर्व बैंक ने इस सप्ताह के शुरू में कोविड- 19 की चुनौती को देखते हुये देश में स्वास्थ्य ढांचे और सेवाओं को मजबूत बनाने के लिये 50,000 करोड़ रुपये के कर्ज की शुरुआत की है। इसके तहत बैंक स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियों को कर्ज देने के लिए केंद्रीय बैंक से मार्च 2022 तक रेपो दर पर उधार ले सकते हैं।

योजना के तहत बैंक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम करने वाली तमाम कंपनियों को नया कर्ज उपलब्ध करा सकेंगे।

टीका विनिर्माता हों अथवा टीका के आयातक, आपूर्तिकर्ता हों। प्राथमिकता वाले चिकित्सा उपकरणों के आपूर्तिकर्ता हों, अस्पताल और डिस्पेंसरी, नैदानिक केन्द्र अथवा पैथालॉजी लैब सभी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। रिजर्व बैंक की इस सुविधा के तहत बैंक आक्सीजन और वेंटीलेटरों का विनिर्माण आपूर्तिकताओं, कोविड संबंधी टीका और दवाओं का आयात करने वाली कंपनियों, कोविड-संबंधी सामान के रखरखाव की सेवायें देने वालें और मरीजों को इलाज के लिये भी वित्तीय सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे।

बहरहाल, रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस खिड़की सुविधा के तहत बैंकों द्वारा ली जाने वाली राशि के एवज में योजना की परिपक्वता तक उस विशिष्ट वर्ग को रिण उपलब्ध कराते रहना होगा।

इसके लिये बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की रिण सुविधा का लाभ मिलेगा। इस तरह के कर्ज को 31 मार्च 2022 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र माना जायेगा।

इस तरह के कर्ज को उनकी वापसी अथवा परिपक्वता अवधि तक जो भी पहले हो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का कर्ज माना जायेगा।

पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की खातिर 16 मई तक के लिए रेमडेसिविर का आवंटन कर दिया गया हैः गौड़ा

नई दिल्लीः केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि देश भर में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा रेमडेसिविर की सहज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को 16 मई तक के लिए इस दवा का आवंटन कर दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को कहा था कि रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 1.03 करोड़ शीशियां प्रति माह कर दी गई है जो पहले 38 लाख शीशियां प्रति माह थी। उन्होंने शुक्रवार को ट्विटर पर लिखा, हर राज्य में रेमडेसिविर की जरूरत को देखते हुए और उसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए, 16 मई, 2021 तक के लिए रेमडेसिविर का आवंटन कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि देश में रेमडेसिविर की सहज आपूर्ति होती रहे ताकि महामारी के इस समय में किसी मरीज को मुश्किल का सामना न करना पड़े।

HDFC का चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 31% बढ़कर 5,669 करोड़ रुपए

नई दिल्लीः आवास वित्त क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने शुक्रवार को बताया कि मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में उसका एकीकृत शुद्ध मुनाफा 31 प्रतिशत बढ़कर 5,669 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 4,342 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था। एचडीएफसी ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि वर्ष 2020-21 की जनवरी-मार्च अवधि में उसकी एकीकृत आय दोगुनी से भी अधिक यानी 35,754 करोड़ रुपए हो गई जो कि वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि में 16,632 करोड़ रुपए रही थी। आलोच्य तिमाही में इस आवास वित्त कंपनी की ब्याज आय घटकर 10,879 करोड़ रुपए रह गई जो एक साल पहले की इसी अवधि में 11,391 करोड़ रुपए थी। कंपनी की जीवन बीमा कारोबार से प्रीमियम और अन्य परिचालन आय 11,530 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,635 करोड़ रुपए हो गई। बहरहाल, पूरे वित्त वर्ष के लिए एचडीएफसी का शुद्ध लाभ एक साल पहले के 22,826 करोड़ रुपए से घटकर 20,488 करोड़ रुपए रह गया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एचडीएफसी की एकीकृत आय बढ़कर 1,39,071 करोड़ रुपए हो गई। इससे पिछले साल उसकी कुल आय 1,01,796 करोड़ रुपए रही थी।

50,000 करोड़ रुपए की कर्ज सुविधा से अस्पतालों की बिस्तर में क्षमता में होगी वृद्धि

मुंबईः

निर्धारक एजेंसी क्रिसिल ने शुक्रवार को कहा कि रिजर्व बैंक की 50,000 करोड़ रुपए की विशेष कर्ज सहायता योजना अस्पतालों की बिस्तर क्षमता 20 प्रतिशत बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस ऋण पर ब्याज दर सस्ता होगा। क्रिसिल ने कहा कि कोविड-19 स्वास्थ्य देखरेख बुनियादी ढांचा को बढ़ाने के लिए बैंकों को प्राथमिकता-क्षेत्र के उधार के तहत दी जाने वाली सहायता, उपचार क्षमता को बढ़ाने और दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगी। कोविड-19 की लहर के बीच देश में स्वास्थ्य देखरेख बुनियादी ढांचे की बड़े हिस्से में भारी कमी महसूस की जा रही है, जहां क्षमता में कमी उजागर हुइ है। देश में नए संक्रमितों की संख्या एक दिन में चार लाख के आंकड़े से ऊपर चल रही है। प्रति दिन करीब 3,500 लोगों की मौत हो रही है । रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन देकर इस सुविधा को शुरु किया है। रेटिंग एजेंसी के एक परिपत्र में कहा अस्पताल इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से हो सकते हैं क्योंकि इस वित्तपोषण से देश में अस्पताल की बेड क्षमता में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इस योजना के सौजन्य से बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वे ऋण देने की वर्तमान दरों से कम दर पर स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए उधार दें।

उन्हें इसके लिए धन मार्च 2022 तक रेपो दर पर उपलब्ध होगा। इसने कहा कि मौजूदा समय में, अस्पताल अपने उधार के लिए ब्याज के बतौर 11 प्रतिशत तक का भुगतान करते हैं, और नई योजनाओं के तहत नया ऋण 3.50 प्रतिशत तक सस्ता होगा।

क्रिसिल के मुख्य रेटिंग अधिकारी सुबोध राय ने कहा, कम लागत पर धन की उपलब्धता बढ़ने से अस्पतालों को बेड की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन भंडारण, आईसीयू और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को पहले ही सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है।

सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन तेजी, 257 अंक चढ़कर 49,200 से ऊपर बंद

मुंबई,

वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख और कंपनियों के बेहतर परिणाम से देश के शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन तेजी का रुख रहा। एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी और भारती एयरटेल के शेयरों में बढ़त से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 257 अंक चढ़कर बंद हुआ। अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपये में 27 पैसे की जोरदार बढ़त से निवेशकों की धारणा को बल मिला। बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स कारोबार की समाप्ति पर 256.71 अंक यानी 0.52 प्रतिशत ऊंचा रहकर 49,206.47 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी सूचकांक 98.35 अंक यानी 0.67 प्रतिशत बढ़कर 14,823.15 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में 2.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ एचडीएफसी में सबसे ज्यादा लाभ दर्ज किया गया। एचडीएफसी का एकीकृत शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में 31 प्रतिशत बढ़कर 5,669 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके साथ ही बजाज फिनसर्व, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, आईटीसी, अल्ट्रा टेक सीमेंट और ओएनजीसी के शेयरों में भी लाभ रहा। इसके विपरीत बजाज आटो, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के शेयरों में दो प्रतिशत तक की गिरावट रही। इस सपताह के दौरान सेंसेक्स में कुल मिलाकर 424.11 अंक यानी 0.86 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गइ 'जबकि निफ्टी में इस दौरान 192.05 अंक यानी 1.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जियोजित फाइनेंसियल सविर्सिज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''वैश्विक बाजारों के समर्थन से बाजार में कारोबार की शुरुआत अच्छी बढ़त के साथ हुई। अमेरिका और यूरोप के देशों में आने जाने पर प्रतिबंधों में ढील दिये जाने से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख बना रहा। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े बेहतर आने से पश्चिमी बाजारों में आर्थिक स्थिति में तेज सुधार का संकेत मिलता है।'' उधर, धातु कंपनियों के शेयरों में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। धातु क्षेत्र में सकारात्मक परिदृश्य बना हुआ है। वहीं मिड-कैप वाले शेयरों में भी सुधार रहा। बीएसई में धातु, मूल धातु, दूरसंचार, बिजली, रियल्टी, तेल एवं गैस, वित्त क्षेत्र के सूचकांक में 5.29 प्रतिशत तक की तेजी रही जबकि टिकाऊ उपभोक्ता सामान, पूंजीगत सामान और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गिरावट का रुख रहा। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई और हांग कांग के बाजारों में गिरावट रही जबकि टोक्यो और सोल के शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख रहा। यूरोप के शेयर बाजारों में मध्यान्ह के समय लाभ की स्थिति बनी हुई थी।

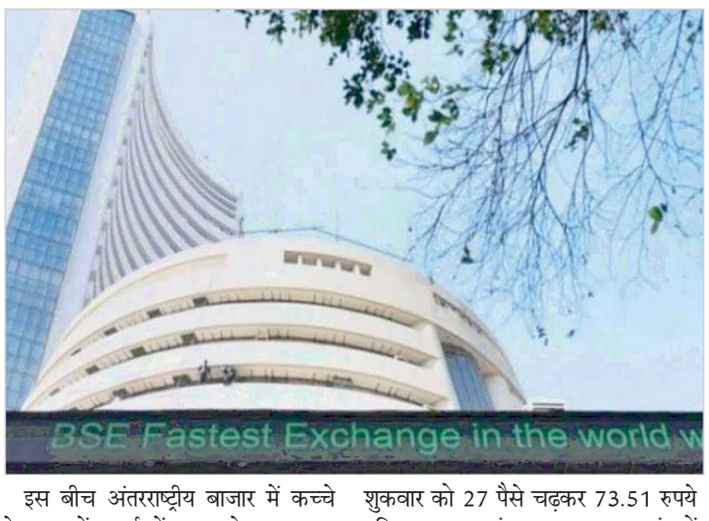

इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड तेल का भाव 0.25 प्रतिशत गिरकर 67.92 डालर प्रति बैरल पर रहा। वहीं अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डालर के मुकाबले रुपया लगातार दूसर दिन बढ़त में रहकर शुकवार को 27 पैसे चढ़कर 73.51 रुपये प्रति डालर पर बंद हुआ। बाजार आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों में 1,222.58 करोड़ रुपये के शुद्ध लिवाल रहे।

कोरोना से बिगड़ी मॉल की आर्थिक हालत, 40 से 50% घटा किराया

बिजनेस डेस्कः

कोरोनावायरस की महामारी का असर मॉल पर बहुत ज्यादा पड़ा है। मॉल में पट्टे पर दुकानें देने में मदद करने वाले सलाहकारों के मुताबिक साल की पहली तिमाही में बड़े शहरों में मॉल के किराये 40-50 फीसदी तक घटे हैं और आगे इनमें ज्यादा गिरावट के आसार हैं। पिछले एक दशक में किराये में यह सबसे तेज गिरावट बताई जा रही है। मॉल प्रबंधन और सलाहकार कंपनी बियॉन्ड स्क्वैरफीट के संस्थापक सुशील एस डूंगरवाल बताते हैं, ज्यादातर मॉल ने न्यूनतम गारंटी की जगह शुद्ध राजस्व हिस्सेदारी मॉडल अपना लिया है, जिससे डेवलपरों को मिलने वाला असल किराया कोविड महामारी से पहले के मुकाबले 40-50 फीसदी कम हो गया है। न्यूनतम गारंटी का मतलब यह है कि मॉल में दुकान लेने वाले का कारोबार कम हो या ज्यादा, उसे मॉल डेवलपर को एक तय किराया ही देना होगा। राजस्व हिस्सेदारी मॉडल में दुकानदार को अपनी कमाई मॉल डेवलपर के साथ बांटनी पड़ती है। अनिश्चित और अप्रत्याशित माहौल के कारण न्यूनतम गारंटी के बजाय राजस्व हिस्सेदारी मॉडल अपना लिया गया ताकि कारोबार चलता रहे। डूंगरवाल ने बताया कि बेंगलूरु, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एक जैसा असर दिखा है। उन्होंने यह बताया कि मॉल का किराया प्रमुख बाजारों के किराए से भी अधिक घटा है। ऐनारॉक रिटेल ने हाल ही में कहा था कि 2021 की पहली तिमाही में दिल्ली के खान मार्केट में औसत मासिक किराया 2020 की पहली तिमाही के मुकाबले 8 से 17 फीसदी तक घटा है। मुंबई के प्रमुख बाजारों में भी किराया 5 से 10 फीसदी लुढ़का है। मुंबई के एक अन्य सलाहकार ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि मौजूदा हालात के कारण मॉल स्टोर मालिकों को 6 से 12 महीने यानी पहले से लंबी अवधि की राजस्व हिस्सेदारी का विकल्प दे रहे हैं। उस सलाहकार ने कहा, महामारी से पहले राजस्व हिस्सेदारी की अवधि तीन से चार महीने होती थी। अब राजस्व हिस्सेदारी का ही रास्ता बचा है।

किराया माफी को लेकर राय जुदा

पिछले लॉकडाउन में ज्यादातर मॉल मालिकों ने अपने किराएदारों का किराया माफ कर दिया था मगर इस बार राय बंटी हुई है। कुछ किराया छोड़ने की योजना बना रहे हैं और दूसरे इसके लिए तैयार नहीं हैं। उदाहरण के लिए एनसीआर की एक प्रमुख मॉल डेवलपर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अप्रैल और मई या लॉकडाउन तक का किराया माफ करने पर विचार चल रहा है।

गूगल ने यूजर्स को डेटा उपयोग को जानने के लिए अधिक नियंत्रण प्रदान किए

नई दिल्ली।

ऐप्पल द्वारा यूजर्स को ऐप डेवलपर्स के साथ उनके डेटा शेयरिंग पर अधिक नियंत्रण दिए जाने के बाद अब गूगल ने गूगल प्ले में एक आगामी सुरक्षा अनुभाग (सेफ्टी सेक्शन) की पूर्व-घोषणा की है, जो लोगों को ऐप को एकत्र या साझा करने वाले डेटा को समझने में मदद करेगा।

2022 की दूसरी तिमाही से नया ऐप सबमिशन और ऐप अपडेट डेवलपर्स को यह जानकारी शामिल करने के लिए कहेगा कि वह किस तरह के डेटा ऐप इकट्ठा करते हैं, यह कैसे संग्रहीत किया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। गूगल डेवलपर्स से यह पूछेगा कि किस प्रकार का डेटा एकत्र किया गया है, जिसमें यूजर्स के सटीक स्थान, संपर्क, व्यक्तिगत जानकारी (नाम, ईमेल पता), फोटो और वीडियो, ऑडियो फाइलें और भंडारण फाइल आदि शामिल हैं। वह इस प्रश्न पूछेगा कि इन्हें किस तरह से संग्रहीत किया जाता है। कंपनी डेवलपर्स से यह भी पूछेगी कि डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है, जिसमें ऐप कार्यक्षमता और निजीकरण जैसी चीजें शामिल है। एंड्रॉएड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में उत्पाद मामलों के उपाध्यक्ष सुजान फ्रेइ ने एक बयान में कहा, स्क्रीनशॉट और डिस्क्रिप्शन जैसे ऐप डिटेल्स के समान डेवलपर्स अपने सेक्शन में बताई गई जानकारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। गूगल प्ले एक पॉलिसी पेश करेगा, जिसके लिए डेवलपर्स को सटीक जानकारी प्रदान करनी होगी। उन्होंने कहा, अगर हमें पता चलता है कि एक डेवलपर ने उनके द्वारा प्रदान किए गए डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और नीति का उल्लंघन किया जा रहा है, तो हमें इसे ठीक करने के लिए डेवलपर की आवश्यकता होगी। जो एप्लिकेशन अनुपालन नहीं करेंगे, वे नीति प्रवर्तन (पॉलिसी इन्फॉर्समेंट) के अधीन होंगे। गूगल ने कहा कि वह इस बात को उजागर करने के लिए नए तत्वों को पेश करेगा कि क्या ऐप में डेटा एन्क्रिप्शन जैसी सुरक्षा प्रथाएं हैं।

कोविड से प्रभावित व्यापारियों की मदद के लिए कैट ने वित्त मंत्री सीतारमण से किया आग्रह

नई दिल्ली।

देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन, कर्फ्यू, रात्रि कर्फ्यू और इसी तरह की अन्य पाबंदियों के चलते पिछले 40 दिनों में घरेलू व्यापार को लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे एक पत्र में देश भर के व्यापारियों के लिए ने तत्काल वित्तीय राहत उपायों और जीएसटी और आयकर के तहत विभिन्न वैधानिक देय तारीखों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है।

कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में जीएसटी एवं आय कर की कुछ तारीखों को आगे बढ़ाने की सराहना करते हुए कहा कि, देश में लॉक डाउन के चलते दुकाने एवं मार्केट पूरी तरह से बंद हैं, जिसके कारण उनका धन आना बंद हो गया है, जबकि विभिन्न प्रकार की पारिवारिक और व्यापारिक जरूरतें जिसमें कर्मचारियों को वेतन, दुकानों और गोदामों के किराए सहित विभिन्न खचरें के लिए अपनी पूंजी खाने के लिए मजबूर कर दिया है, जो उनके व्यवसाय के भविष्य के लिए बहुत विनाशकारी है। कैट ने केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण से आग्रह किया कि, सरकार को कुछ कदम तत्काल उठाने की आवश्यकता है जिससे कुछ समय के लिए व्यापारियों पर से वित्तीय भार और नियमों के पालन का बोझ कम हो सके। वहीं जीएसटी और आयकर के तहत सभी वैधानिक तिथियां जिनके द्वारा या तो कर का भुगतान किया जाना है या रिटर्न दाखिल करना है को 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया जाए। जीएसटी के तहत फॉर्म जीएसटीआर -3 बी के स्थान को चालान को कर भुगतान का दस्तावेज माना जाए , इससे करदाता को कर का जल्द भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकार को भी समय पर कर मिलेगा। कैट ने यह भी आग्रह किया कि, बैंकों को लॉकडाउन की अवधि के लिए व्यापारियों से ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए और छह महीने की का एक मोरोटोरियम अवधि दी जानी चाहिए, जिसमें ऋण की ईएमआई का भुगतान करने या लिए गए ऋणों को चुकता करने पर रोक लगाई जाए।

'कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण एक मात्र विकल्प'

मुंबई

देश में कोरोना संक्रमण के प्रति दिन सामने आ रहे कुल नए मामलों में से लगभग पचास प्रतिशत नए मामले ग्रामीण इलाकों में से आ रहे है जिससे चिंता बढ़ गई है। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में भीषण रूप से बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने एक मात्र समाधान तेजी से टीकाकरण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के कुल नए मामलों में देश में सर्वाधिक प्रभावित 15 जिलों के संक्रमितों का हिस्सा मार्च में 55 प्रतिशत था। इन जिलों का हिस्सा मई में घटकर 26.3 प्रतिशत रह गए है। इसका मतलब है कि कोरोना संक्रमण अब पूरे देश में फैल गया है। एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने कहा कि सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि मई में 48.5 प्रतिशत कोरोना संक्रमण के नए मामले ग्रामीण इलाकों से रहे। जबकि मार्च के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के मामले 36.8 प्रतिशत थे। उन्होंने कहा, ''वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने का एक मात्र विकल्प बड़े पैमाने पर टीकाकरण करना है। कोरोना संक्रमण से रिकवरी लोगों के जल्द से जल्द बाहर निकलने पर निर्भर करती है। ऐसा तभी संभव है जब बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एक बार हम फिर टीकाकरण पर जोर देते हैं।''घोष ने कहा, ''अबतक 16.5 करोड़ लोगों को पहला टीका लगा गया है। जिसमे से 13.1 करोड़ लोगों को पहला और 3.15 करोड़ लोगों की दूसरा टीका लग चुका हैं। दूसरा टीका लगवाने वाली लोगों संख्या घटकर 19.5 प्रतिशत हो गई है। वही अप्रैल में जहां प्रतिदिन 28 लोगों को कोरोना का टीका लग रहा था अब केवल 17 लाख लोगों को प्रतिदिन कोरोना का टीका लग रहा है।'' उन्होंने कहा यदि हम इसी गति से चले तो हम अक्टूबर तक केवल 15 प्रतिशत आबादी को ही टीका लगा पाएंगे जबकि हर्ड इम्युनिटी के लिए सितंबर तक 55 लाख लोगों को प्रतिदिन टीका लगाने की जरुरत हैं। देश में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 4,14,188 नये मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 2,14,91,598 हो गए जबकि देश में 36 लाख से अधिक मरीज अब भी इस बीमारी की चपेट में हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

WTC फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के लिये टेस्ट टीम का ऐलान, जडेजा-विहारी की वापसी

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम घोषित

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

फिटनेस समस्याओं से पार पा चुके हरफनमौला रविंद्र जडेजा और बल्लेबाज हनुमा विहारी ने अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला के लिए भारत की 20 सदस्यीय टेस्ट टीम में वापसी की है।

चयनकर्ताओं ने अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और अर्जन नगवासवाला को भी स्टैंडबाय के तौर पर टीम में रखा है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने वाले केएल राहुल और कोरोना संक्रमित रिद्धिमान साहा को टीम में रखा गया है, बशर्ते वे पूरी तरह फिट हो जाएं। जडेजा और विहारी को आस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल 18 जून को साउथम्पटन में खेला जाएगा जबकि इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला 4 अगस्त से शुरू होगी।

भारतीय टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, केएल राहुल (फिट होने पर), रिद्धिमान साहा (फिट होने पर)।

स्टैंडबाय: अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान , अर्जन नगवासवाला।

आईपीएल 2021 को स्थगित करने के फैसले का शोएब अख्तर ने किया समर्थन, कहा- एक साल पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी

नई दिल्ली। कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन को बीसीसीआई ने स्थगित करने का फैसला किया था। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बीसीसीआई के इस फैसले को एकदम सही करार दिया है। शोएब ने कहा कि भारत में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और रोजाना लगभग 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, ऐसे समय में आईपीएल को जारी नहीं रखा जा सकता था। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, 'जब मैंने कुछ हफ्ते पहले यह बात कही थी कि आईपीएल को इस साल रोक देना चाहिए, तो उसके पीछे इमोशन थे। और वह यह था कि

भारत में एक राष्ट्रीय प्रलय आ रही है। लोग मर रहे हैं। और मैंने अपील की थी, क्योंकि एक दिन में लगभग 4 लाख केस रिपोर्ट हो रहे थे। ऐसे समय में आईपीएल नहीं हो सकता, धूम-धड़ाका और शो नहीं हो सकते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है कि लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं। लोग साल 2008 से पैसा कमा रहे हैं। अगर वह एक साल नहीं पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो उनको क्या दिक्कत हो जाएगी लोग मर रहे हैं और आप ऐसे में शो नहीं कर सकते। यह एक नेशनल आपदा है। तो एक पड़ोसी होने के नाते, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आईपीएल को रोक दिया जाए।' शोएब अख्तर ने कहा कि बायो-बबल फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए उतना सफल नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान भी कोरोना के कई मामले सामने आए थे और एकदम यही आईपीएल के दौरान भी हुआ। हम इसको यूएई और इंग्लैंड में कर सकते हैं। पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि यहां पर होटल में काम करने वाले लोग सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि वह बायो-बबल में नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट बायो-बबल में हो सकता है, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं, क्योंकि इसमें पूरा विश्व आता है। आईपीएल के छोटा इवेंट नहीं है।

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कोरोना पॉजिटिव निकले मामलों पर दीपक चाहर बोले- किसी ने प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)।

आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में सामने आए कोरोना मामलों पर दीपक चाहर ने सफाई देते हुए कहा है कि टीम ने किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया था और उनको नहीं पता कि क्या गलत हुआ। गौरतलब है कि सीएसके टीम के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी, माइकल हसी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन को स्थगित करने का फैसला किया था।

स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत करते हुए दीपक ने कहा, 'जैसे ही कुछ रिपोर्ट्स पॉजिटिव आईं, तो टीम मैनेजमेंट ने हमको आइसोलेट होने को कहा। हमारे रोज टेस्ट हुए और रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो वह एक बड़ी राहत थी। लेकिन, कोई भी खिलाड़ी घबराया नहीं और सबने मिलकर काफी अच्छे से मैनेज किया। कोई भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन, जाहिर तौर पर मुझे नहीं पता कि क्या गलत हुआ। यह कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने बायो-बबल का अच्छी तरह से पालन किया था। जब आप एक शहर से दूसरे शहर के लिए बबल बनाते हैं, तो यह एक मुश्किल काम होता है। लेकिन, मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि आखिर असल में हुआ क्या।'

दीपक ने कहा कि ऐसे समय में आईपीएल होना चाहिए था। उन्होंने कहा, 'यह बिल्कुल चैलेंजिंग था, लेकिन ऐसे समय में आईपीएल होना जरूरी था। हर तरफ काफी निराशा है, लेकिन कम से कम हम उनको कुछ घंटों के लिए एंटरटेन कर रहे थे। हम पब्लिक के लिए खेल रहे थे और वहीं हमारा मोटिवेशन था।' केकेआर के खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और केकेआर के बीच होने वाले मुकाबले को रिशेड्यूल कर दिया गया था। हालांकि, उसके बाद कई केस सामने आए और टूर्नामेंट को स्थगित करना पड़ा।

आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों की मेजबानी करने के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने की पेशकश, बीसीसीआई को दिया यह ऑफर

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

आईपीएल 2021 के स्थगित होने के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए मुकाबले कब होंगे और किस जगह पर खेले जाएंगे। इंग्लैंड की चार काउंटी टीमों ने इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के बचे हुए मैच की मेजबानी करने की इच्छा जाहिर करते हुए ईसीबी को लेटर लिखा था। वहीं, अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को अपने देश में इस टी-20 लीग के मुकाबले करवाने का ऑफर दिया है। श्रीलंका ने कहा है कि वह सितंबर में आईपीएल की मेजबानी करने को तैयार है।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमिटी के चीफ अर्जुना डी सिल्वा ने 'डेक्कन क्रोनिकल' के साथ बातचीत करते हुए कहा, 'हां, हम आईपीएल के मैचों को करवाने के लिए सितंबर के महीने में विंडो दे सकते हैं। हमने सुना है कि यूएई उनका एक ऑप्शन है, लेकिन श्रीलंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम श्रीलंका प्रीमियर लीग को जुलाई और अगस्त में होस्ट करने की सोच रहे हैं और मैदान और इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीएल के लिए सितंबर में तैयार रहेगा।' श्रीलंका ने पिछले साल भी आईपीएल की मेजबानी करने की पेशकश की थी, लेकिन बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को यूएई में करवाने का फैसला किया था।

बीसीसीआई हालांकि आईपीएल के बचे हुए मैचों को लेकर जल्द कोई फैसला लेने के मूड़ में नहीं दिख रही है। कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद आईपीएल 2021 को स्थगित करना पड़ा था। इस सीजन 29 मैच खेले गए थे, जबकि लगभग इतने ही मुकाबले अभी और खेले जाने हैं। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने बताया था कि अगर आईपीएल को किसी कारण से कैंसल करना पड़ता है, तो इससे बोर्ड को लगभग 2500 करोड़ का नुकसान होगा।

राजस्थान रॉयल्स के युवा गेंदबाज चेतन सकारिया के पिता को हुआ कोरोना, आईपीएल की कमाई से मिली बड़ी मदद

नई दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स के युवा तेज गेंदबाज चेतन सकारिया के पिता कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उनके पिता कांजीभाई को अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। आईपीएल बायो बबल में कोविड 19 की एंट्री के बाद आईपीएल 2021 को बीसीसीआई ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। उन्हें घर पहुंचने के बाद सीधे अस्पताल जाना पड़ा। सकारिया ने कहा कि वो भाग्यशाली है कि उन्हें समय पर आईपीएल का पेमेंट मिल गया। इस पैसे वो पिता का इलाज करा रहे हैं। चेतन सकारिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे राजस्थान रॉयल्स से मेरा हिस्से का भुगतान कर दिया। मैंने तुरंत पैसे घर भेजे और इससे मेरे पिता को सबसे बड़े समय में मदद मिली। उन्होंने बताया कि उनके पिता एक हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे सकारिया ने कहा कि अगर आईपीएल नहीं होता तो वो अपने पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं कमा पाते। सकारिया ने आगे कहा कि लोग कह रहे हैं कि आईपीएल बंद करो, मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूं, मैं अपने परिवार में एकमात्र रोटी कमाने वाला इंसान हूं। क्रिकेट मेरी कमाई का एकमात्र स्रोत है। मैं अपने पिता को आईपीएल से मिले पैसे की वजह से बेहतर इलाज दे सकता हूं। अगर यह टूर्नामेंट एक महीने के लिए नहीं होता, तो यह मेरे लिए बेहद मुश्किल हो जाता। मैं एक बेहद गरीब परिवार से आता हूं। मेरे पिता ने सारी जिंदगी टेंपो चलाया और आईपीएल की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई।

आईपीएल 2021 क्रिस मौरिस ने बताया बायो बबल में खिलाड़ियों कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्यों इंग्लैंड के क्रिकेटर्स सबसे ज्यादा डरे हुए थे

जोहांसबर्ग। (एजेंसी)।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर क्रिस मौरिस ने बताया कि जब टूर्नामेंट के दौरान बायो बबल में कोविड-19 टेस्ट में खिलाड़ी पॉजिटिव पाए जाने लगे, तो अफरातफरी का माहौल बन गया था। दक्षिण अफ्रीका के इस क्रिकेटर ने कहा कि वह स्वदेश लौटकर राहत महसूस कर रहे हैं। 3 मई को आईपीएल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच मैच खेला जाना था, जिससे पहले केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते इस मैच को स्थगित किया गया। अगले दिन सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाना था, जिससे पहले ऋद्धिमान साहा का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके अलावा चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। इन सबके बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल 2021 को बीच में ही स्थगित करने का फैसला ले लिया।

आईपीएल को स्थगित किए जाने के बाद मौरिस और 10 अन्य दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी स्वदेश लौट गए हैं। आईपीएल में कोविड-19 के छह मामले पाए गए थे, जिसमें चार खिलाड़ी और दो कोच शामिल थे। अभी अपने घर में 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन पीरियड बिता रहे मौरिस ने कहा, 'निश्चित तौर पर मैं राहत महसूस कर रहा हूं।' मौरिस ने कहा कि उन्हें केकेआर के दो खिलाड़ियों के पॉजिटिव पाए जाने के बारे में रविवार की रात को पता चला।

उन्होंने कहा, 'जैसे ही हमें इस बारे में पता चला कि बायो बबल के अंदर खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो सभी ने सवाल करने शुरू कर दिए। हम सभी के अंदर निश्चित तौर पर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई थी।' मौरिस ने कहा, %सोमवार तक जब उन्होंने वह मैच (केकेआर और आरसीबी) स्थगित किया तब तक हमें पता चल गया था कि टूर्नामेंट जारी रखने के लिए दबाव बना हुआ है।' सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा के मंगलवार को पॉजिटिव आने के बाद इस टी20 लीग को स्थगित कर दिया गया था। चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाजी कोच एल बालाजी और बल्लेबाजी कोच माइकल हस्सी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।

मौरिस ने कहा, 'मैं अपनी टीम के डॉक्टर से बात कर रहा था। कुमार संगकारा ने तब इशारा किया और तब हमें पता चला कि अब टूर्नामेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद का माहौल अफरातफरी वाला था। इंग्लैंड के खिलाड़ी खास तौर से घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें इंग्लैंड में होटलों में आइसोलेशन रहने की जरूरत थी और जाहिर था कि उनके पास कमरे नहीं थे।' ऑस्ट्रेलियाई एंड्रयू टाइ की जगह चुने गए गेराल्ड कोएट्जी पिछले सप्ताह ही भारत पहुंचे थे और मौरिस ने कहा कि वह इस युवा तेज गेंदबाज को धीरज बंधा रहे थे क्योंकि वह अधिक घबराया हुआ था। उन्होंने कहा, 'मैं जानता था कि गेराल्ड अधिक घबराया हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि वह अभी 20 साल का है और उसके सामने यह सब कुछ हो गया। मैंने उसे धीरज बंधाने की कोशिश की।'

आकाश चोपड़ा ने चुने आईपीएल 2021 के छह बेस्ट अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी, आवेश खान को बताया बेस्ट

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2021 को 29 मैचों के बाद बीच में सस्पेंड करना पड़ा। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा स्टार हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इन 29 मैचों के आधार पर आईपीएल 2021 के छह बेस्ट भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी चुने हैं। इस लिस्ट में आकाश ने महज एक बल्लेबाज को रखा है, जबकि पांच गेंदबाज हैं। पांच गेंदबाजों में से तीन तो तेज गेंदबाज ही हैं, जबकि एक स्पिनर है। उन्होंने इस लिस्ट में सबसे ऊपर दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज आवेश खान को रखा है, जबकि दूसरे नंबर पर पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल हैं। आकाश ने बताया कि क्यों उन्होंने आवेश को हर्षल से ऊपर रखा है। आकाश चोपड़ा ने कहा कि आवेश खान ने शुरू से लेकर आखिरी तक शानदार गेंदबाजी की। आवेश ने कुल आठ मैच खेले, जिसमें 14 विकेट झटके और 7.70 के इकॉनमी रेट से 231 रन खर्चे। आवेश टी20 फॉर्मेट के हिसाब से ज्यादा महंगे साबित नहीं हुए। वहीं हर्षल पटेल की बात करें, तो उन्होंने भले ही विकेट ज्यादा लिए, लेकिन उनका इकॉनमी रेट 9.17 का रहा है। चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के मैच में हर्षल ने एक ओवर में 37 रन लुटा दिए थे। हर्षल ने सात मैचों में 17 विकेट लिए और इस दौरान 257 रन खर्चे।

महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले की वसीम जाफर ने की जमकर तारीफ, कहा- ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने महेंद्र सिंह धोनी के फैसले की जमकर तारीफ की है। धोनी ने आईपीएल स्थगित होने के बाद ऐलान किया था कि वह चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ी और स्टाफ मेंबर के घर लौटने के बाद ही रांची जाएंगे। माही के इस फैसले पर जाफर ने कहा कि ऐसा काम सिर्फ धोनी ही कर सकते हैं। कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया था।

वसीम जाफर ने अपने ट्विटर पर लिखा, 'वहा पर अंत तक रुक कर और काम को खत्म करके आना, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कर सकते हैं।' धोनी की इस फैसले की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हुई थी। आईपीएल स्थगित होने के बाद सभी टीमों ने बीसीसीआई की मदद से विदेशी खिलाड़ियों को चार्टर्ड फ्लाइट की जरिए उनको घर भेजने का इंतजाम किया था। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया सरकार के नियमों के चलते कंगारू खिलाड़ियों की मालदीव में रहने की व्यवस्था की गई। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मालदीव में क्वारंटाइन पीरियड पूरा करेंगे और जब भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फ्लाइट चालू होगी, तो वह अपने स्वदेश रवाना होंगे।

धोनी की अगुवाई में सीएसके का प्रदर्शन आईपीएल 2021 में बेहद शानदार रहा था और टीम ने खेले 7 मैचों में से 5 में दमदार जीत दर्ज की थी, जबकि सिर्फ 2 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। टीम की तरफ से फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड ने कुछ जबरदस्त पारियां खेलीं थीं, जबकि अंबाती रायडू और रवींद्र जडेजा भी बेहतरीन लय में नजर आए थे। जडेजा ने आरसीबी के खिलाफ खेले मैच में हर्षल पटेल के एक ओवर में 37 रन कूटे थे। गेंदबाजी में दीपक चाहर ने दो मुकाबलों में चार-चार विकेट अपने नाम किए थे।

हमारे खिलाड़ी आईपीएल बायो बबल में सुरक्षित महसूस कर रहे थे: ग्रीम स्मिथ

जोहानिसबर्ग। (एजेंसी)।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के क्रिकेट निदेशक ग्रीम स्मिथ ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भाग ले रहा उनका कोई भी खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा तैयार किये गये जैव सुरक्षित वातावरण (बायो बबल) में असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। बायो बबल में कोविड-19 के कई मामले पाये जाने के बाद आईपीएल को चार मई को स्थगित कर दिया गया था। इस लीग में भाग लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के सभी 11 खिलाड़ी जोहानिसबर्ग रवाना हो चुके हैं।

पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान स्मिथ ने संवाददाताओं से कहा, ''हम किसी भी तरह से कोई फैसला नहीं सुना सकते हैं। खिलाड़ियों से बात की, वे वहां सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनका कहना था कि भारत में जैव सुरक्षित वातावरण का अनुभव वास्तव में बहुत अच्छा रहा। वे किसी भी समय जोखिम महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसी ही प्रकृति कोविड से जुड़ी है। '' भारत में अभी प्रतिदिन चार लाख से अधिक मामले आ रहे हैं तथा हर दिन 4000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। स्मिथ ने कहा कि महामारी के दौरान जोखिम हमेशा बना रहता है और आयोजकों को दोष नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, ''कई बार आप जो चाहते हो वह आप नहीं कर सकते हो। बायो बबल को कभी पूर्ण सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। जब आपके देश में कोविड का प्रकोप हो तो जोखिम हमेशा बना रहता है।

दुर्भाग्य से यह जब बायो बबल में घुसता है तो फिर क्या होगा यह भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है। '' स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की सुरक्षित वापसी के लिये बीसीसीआई के प्रयासों की भी सराहना की। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी शुक्रवार को स्वदेश लौट गये और अभी अपने घरों में पृथकवास पर हैं। उन्होंने कहा, ''बीसीसीआई ने जिस तरह से खिलाड़ियों की देखभाल की वह अनुकरणीय है। हमारे खिलाड़ियों के लिये थोड़ा आसान था क्योंकि हमारी सीमाएं बंद नहीं थी और उनके लिये व्यावसायिक उड़ान उपलब्ध थी।

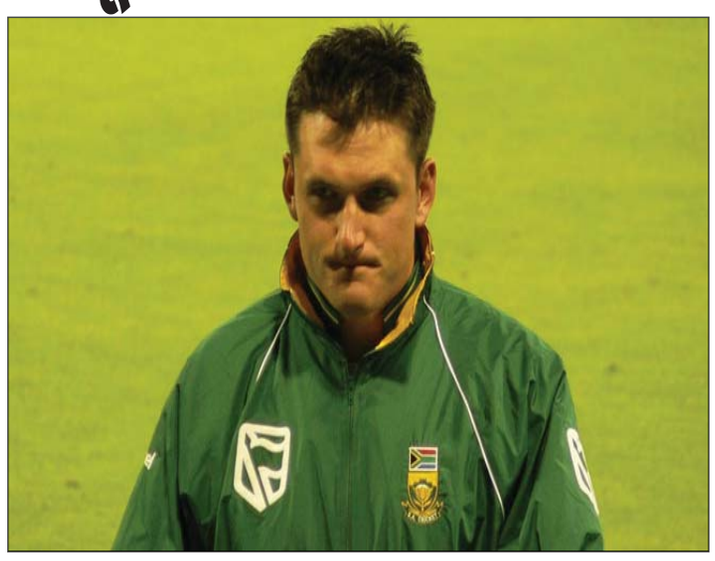

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

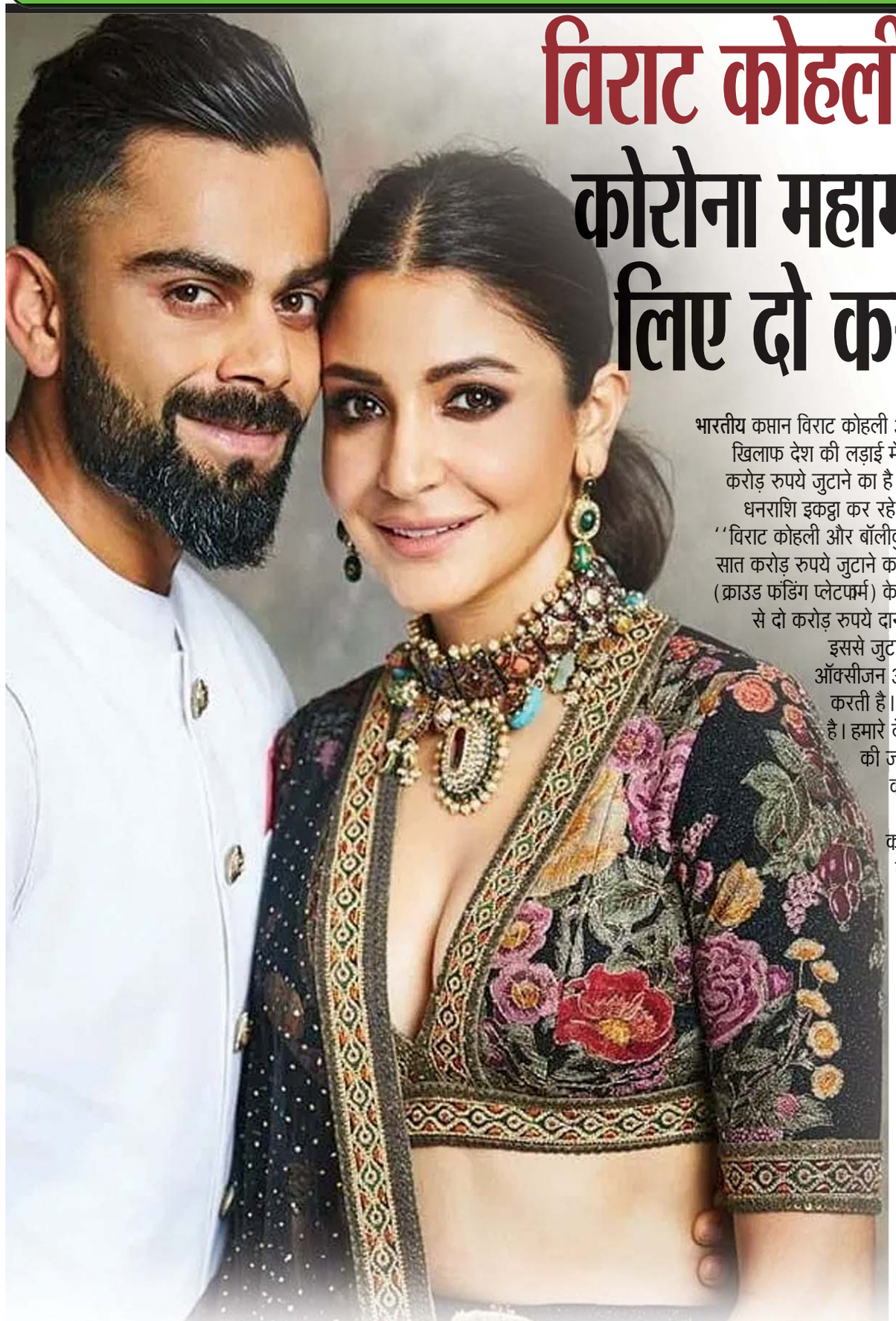

विराट कोहली और अनुष्का ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए दो करोड़ की मदद की

भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनकी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद के लिये दो करोड़ रुपये का दान किया है। उनका लक्ष्य सात करोड़ रुपये जुटाने का है। ये दोनों आम जनता से धन जुटाने वाली संस्था केटो के जरिये यह धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं। कोहली और अनुष्का की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ''विराट कोहली और बॉलीवुड सुपरस्टार अनुष्का शर्मा का भारत में कोविड राहत कोष के लिये सात करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।'' इसमें कहा गया है, ''वे लोगों से धन जुटाने वाले मंच (क्राउड फंडिंग प्लेटफार्म) केटो के जरिये एक अभियान शुरू कर रहे हैं और उन्होंने अपनी तरह से दो करोड़ रुपये दान किये हैं।'' यह अभियान केटो पर सात दिन तक चलाया जाएगा। इससे जुटायी गयी धनराशि एसीटी ग्रांट्स नामक संस्था को दी जाएगी जो कि ऑक्सीजन और चिकित्सा से जुड़ी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में काम करती है। कोहली ने कहा, ''हमारा देश इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारे देश को अभी हम सभी के एकजुट होने और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने की जरूरत है। मैं और अनुष्का पिछले एक साल से लोगों की पीड़ा देखकर आहत हैं।'' कोहली ने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने वायरस के खिलाफजंग में अधिक से अधिक लोगों की मदद करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, ''हम अधिक से अधिक लोगों की मदद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत को अभी हमारी सबसे अधिक सहायता की जरूरत है। हमनेइस विश्वास के साथ धन जुटाने का बीड़ा उठाया है हम जरूरतमंद लोगों के लिये पर्याप्त धन जुटा सके। हमें विश्वास है कि लोग अपने देशवासियों की मदद के लिये आगे आएंगे। हम एकजुट हैं और हम इससे पार पाने में सफल रहेंगे।

रणबीर कपूर इस हीरोइन को किस करते समय हो गए थे बेकाबू

चॉकलेट बॉय रणबीर कपूर बेहद रोमांटिक हैं। दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के साथ उनका खूब रोमांस चला था। तो ऐसे ही दिलफेंक हीरो का जब फिल्म ये जवानी है दीवानी में एक किसिंग सीन फिल्माया गया तो वे बेकाबू हो गए थे और ये हीरोइन दीपिका पादुकोण नहीं थी। इस हीरोइन का नाम था एवलिन शर्मा। एवलिन को रणबीर कपूर डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी किस करते रहे और उन्हें थोड़ी देर बाद समझ आया कि कट बोला जा चुका है। वैसे रणबीर से जुड़े लोगों का कहना था कि वे सीन में इतना डूब गए थे कि कट की आवाज ही नहीं सुन पाए और यह गड़बड़ी हो गई। जर्मन मॉडल और एक्ट्रेस एविलन शर्मा ने बॉलीवुड में 'फॉम सिडनी विद लव' से शुरुआत की थी। यारिया, हिंदी मीडियम, जब हैरी मेट सेजल जैसी कुछ फिल्मों में वे दिखाई दीं, लेकिन अभी तक उनकी ठोस पहचान नहीं बन पाई।

मेरे लिए सही इंसान नहीं थे अश्मित

बिग बॉस फेम और एक्ट्रेस महक चहल और अश्मित पटेल ने भी 5 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था। दोनों ने सगाई भी की, लेकिन फिर उन्होंने अपनी सगाई तोड़ दी थी। महक और अश्मित के ब्रेकअप की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब इस मुद्दे पर एक बार फिर महक ने अपने दिल की बात कही है। अश्मित पटेल के साथ ब्रेकअप के बारे में महक ने कहा कि वो इस रिश्ते को खत्म करने के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानती हैं। उन्होंने कहा कि, जब आप किसी के साथ रहने लगते हैं, उसे करीब से जानने लगते हैं तब आपको उसको बेहतर ढंग से जान पाते हैं। मुझे लगता है कि अश्मित पटेल मेरे लिए सही इंसान नहीं थे। ब्रेकअप के बाद से मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद रहे। मैंने उन्हें अपने दिल की बात कही। लॉकडाउन के चलते मैंने काफी सारा वत गोवा में बिताया और सिर्फ जरूरत पड़ने पर मुंबई आती थी। महक ने कहा, वत की सबसे अच्छी बात यही है कि ये सब ठीक कर सकता है। हालांकि कोरोना के चलते कोई काम नहीं था तो ये आसान नहीं था, लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूं। महक ने ये भी बताया कि अगर अश्मित से उनका ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो वो गोवा नहीं जाती।

सलमान खान की फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' का अब यह हो सकता है नाम

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की कई फिल्में इस साल रिलीज होने की कतार में हैं। हाल में सलमान अपनी फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' को लेकर सुर्खियों में थे। बीते दिनों खबर आई थी कि सलमान की इस फिल्म का नाम बदल सकता है। बताया जा रहा है कि विवादों से बचने के लिए इस फिल्म का नाम बदलने का विचार किया जा रहा है। अब जानकारी सामने आ रही है कि सलमान की इस फिल्म का नाम बदल कर 'भाई जान' रखा जा सकता है। खबरों के मुताबिक, 'कभी ईद कभी दिवाली' के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म का नया टाइटल 'भाई जान' रखा है। साजिद नाडियाडवाला को लगता है कि वह केवल सलमान हैं, जो 'भाई जान' की उपाधि को धारण कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 'कभी ईद कभी दिवाली' का संभावित नाम रखा गया है। उन्हें लगता है कि फिल्म का यह टाइटल फिल्म के विषय को न्यायसंगत ठहराएगा। बताया जा रहा है कि मेकर्स फिल्म के टाइटल को 'भाई जान' रखने को लेकर सलमान से बातचीत में लगे हैं। सलमान को लगता है कि मेकर्स को 'कभी ईद कभी दिवाली' के टाइटल के साथ दर्शकों के बीच जाना चाहिए। फिल्म में पूजा हेगड़े फीमेड लीड किरदार में नजर आएंगी। सलमान के बहनोई आयुष शर्मा और जहीर इकबाल भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। 'टाइगर 3' की शूटिंग खत्म करने के बाद सलमान इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इस फिल्म का निर्देशन फरहाद सामजी द्वारा किया जाएगा। इस फिल्म में सलमान पहली बार अभिनेत्री पूजा के साथ रोमांस करते नजर आएंगे।

मेरा संघर्ष कम नहीं

दवंगत अभिनेता अमरीश पुरी के पोते अभिनेता वर्धन पुरी ने कहा है कि उनका संघर्ष किसी भी अन्य अभिनेता से अलग नहीं रहा है क्योंकि उनके दादा तब उनके पास नहीं थे जब उन्होंने सिनेमा में कदम रखा था। उन्होंने बताया, 'इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन यह आसान नहीं था मेरे दादाजी का निधन तब हो गया था जब मैं बहुत छोटा था और वह मेरे लिए कॉल करने या फिल्म निर्माताओं के कार्यालयों में ले जाने के लिए मौजूद नहीं थे।' 2019 में फिल्म 'ये साली आशिकी' से अपनी शुरूआत करने वाले अभिनेता ने अपने दादा के साथ अपनी शानदार यादों को याद किया। उन्होंने कहा ''हर कोई यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि दादू क्या थे। मेरे पास सबसे अच्छी यादें हैं, जब हम एक साथ फिल्में देखा करते थे। मैं लंबे समय से उस समय को वापस जीना चाहता हूं। मुझे चैप्लिन की फिल्में देखना याद आता है, उस वक्त हम साथ बैठकर नाश्ता करते और ब्रेक के दौरान परिवार से बातचीत करते थे।' वर्धन आज एक साल और बड़े हो गए और उन्होंने याद किया कि उनके दादाजी उनके जन्मदिन समारोह का एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने कहा, कि बचपन में, मेरा परिवार, दोस्त और मैं चाचा के खेत मड आइलैंड जाते थे और पूरे दिन खेलों में भाग लेते थे। मेरे दादा-दादी उसने जज हुआ करते थे और पुरस्कार देते थे। यह सबसे अच्छा था। अभिनेता की योजना इस साल कोविड से प्रभावित लोगों की मदद करने की है। उन्होंने कहा, 'यह जन्मदिन मैं कोविड से पीड़ित रोगियों को चिकित्सा सेवा देने के लिए एक एनजीओ के साथ हूं। इसके अलावा, रात के खाने के बाद मैं अपने माता-पिता, मेरी बहन साची, उनके पति निशांत और मेरे साथ रहने वाले मेरे सहायकों के साथ समय बिताने की योजना बना रहा हूं। उसके बाद, मैं करीबी दोस्तों और परिवार के साथ एक जूम कॉल पर मिलूंगा और शायद कुछ गेम खेलूंगा। मैं इस बार सरलता से मनाना चाहता हूं। मैं हर चीज के साथ जश्न मनाने के मूड में नहीं हूं।' अभिनेता अब अगली फिल्म 'द लास्ट शो' में दिखाई देंगे।

राखी सावंत का दावा-

मुझे और मेरी फैमिली को कभी नहीं होगा कोरोना

ड्रामा क्वीन राखी सावंत अक्सर ऐसे बयान देती है कि लोग हैरान हो जाते हैं। इन दिनों देश में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रखी है। हर दिन लाखों लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इसी बीच राखी सावंत ने दावा किया है कि वो कोरोनावायरस की चपेट में नहीं आ सकती हैं। इस दावे के पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। राखी सावंत का एक वीडिटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राखी दावा कर रही हैं कि उन्हें या उनकी फैमिली को कभी कोरोना नहीं होगा, क्योंकि उनके शरीर में यीशू का पवित्र लहू है। राखी के वीडियो पर तमाम तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं। वहीं राखी ने देश में वैक्सीन की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि उनके हिस्से की वैक्सीन जरूरतमंद को लगा दी जाए। राखी ने निक्की तंबोली के भाई के निधन पर भी दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया कि बिग बॉस में अक्सर निक्की अपने भाई के बारे में बात करती थीं। राखी ने कंगना के ट्विटर सस्पेंड होने के मुद्दे पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि, इस तरह की भड़काऊ बातें करना भी देश के साथ गद्दारी करने जैसा है।

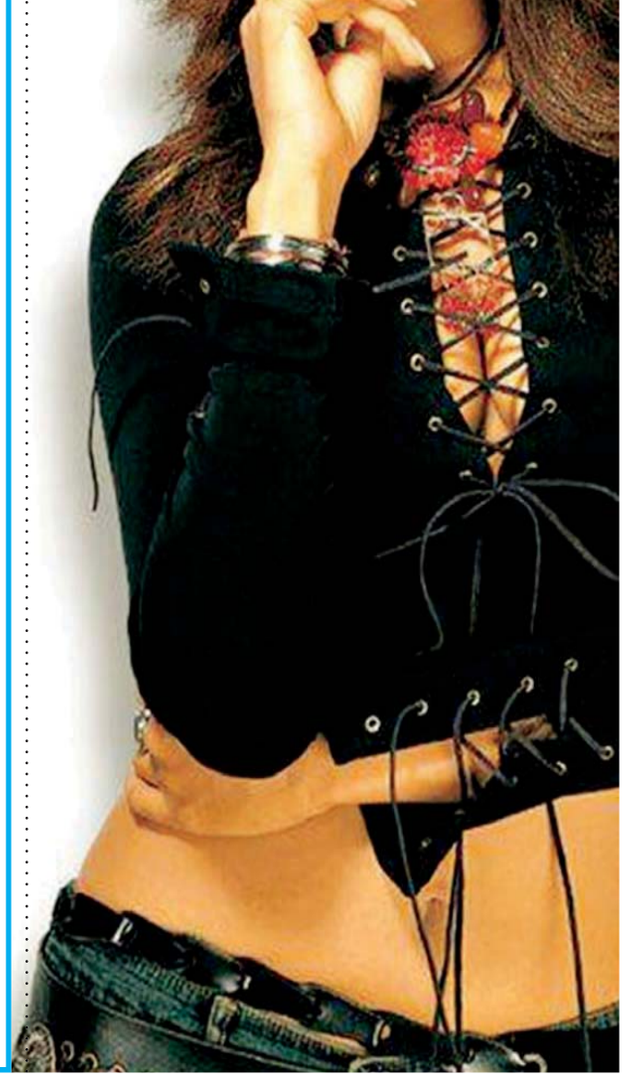

कम पानी में भी हो सकती है धान की अच्छी पैदावार

सूखा प्रतिरोधी धान की खेती करना अब मुमकिन हो गया है। शुक्र है कि गेहूं की तरह अब चावल उगाने के लिए तकनीक उपलब्ध हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि धान के खेत को हमेशा पानी से भरा हुआ रखे बिना भी इसकी खेती की जा सकती है। नई तकनीक से धान की फसल के लिए पानी की जरूरत में 40 से 50 फीसदी तक कम करने में मदद मिलेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और फिलिपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) ने संयुक्त रूप से यह तकनीक विकसित की है। इस परियोजना में कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) की भी भागीदारी है। कटक स्थित संस्थान ने ही धान की वैसी किस्मों की पहचान की है जिन्हें दूसरी फसलों की तरह कुछ दौर की सिंचाई के जरिए उगाया जा सकता है। इसने ऐसी कृषि पध्दतियों की भी खोज की है जिसके जरिए धान की ऐसी किस्मों से करीब-करीब उतनी उपज हो सकती है जितनी सामान्य तौर से ज्यादा पैदावार वाली धान की होती है। तकनीकी तौर पर यह एरोबिक राइस कल्टिवेशन कहलाता है। इस तकनीक में धान के खेत में स्थिर पानी की जरूरत नहीं होती और न ही धान के छोटे पौधे तैयार करने की आवश्यकता होती है जैसा कि आम तौर पर होता है और बाद में उसे उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। इस तकनीक में कुशलता से तैयार किए गए खेतों में सीधे बीज बो दिए जाते हैं और इस तरह श्रम लागत की भी बचत हो जाती है।

सीआरआरआई के निदेशक टी. के. आद्या के मुताबिक, एपो नाम के ब्राजील के एरोबिक राइस को दुनिया के सबसे अच्छा एरोबिक राइस माना जाता है। एपो को भारतीय धान के साथ क्रॉसब्रीड करवाकर ऐसी किस्म तैयार की जा रही है जो भारतीय कृषि की पारिस्थितिकी के लिए उपयुक्त हो। इन किस्मों में 40 फीसदी कम पानी का इस्तेमाल होता है और अच्छे प्रबंधन के जरिए यह 4-5 टन धान की उपज हो सकती है। एरोबिक स्थितियों में (बिना स्थिर पानी के) उगाए जाने वाले धान की पैदावार सामान्य तौर पर प्रति हेक्टेयर दो टन से कम होती है। एपो जर्मप्लाज्म समेत एरोबिक धान तैयार करने की लिए ब्रीडिंग सामग्री आरआरआरआई से प्राप्त की गई थी। नई किस्मों से कई का परीक्षण खेत में किया जा चुका है। इनमें से एक किस्म शहभागी धान आईआरआरआई इंडिया सीआरआरआई ब्रीडिंग नेटवर्क के जरिए पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है ताकि सूखा प्रभावित इलाकों में इसकी खेती हो सके। एक किलोग्राम धान के उत्पादन में सामान्यतः तीन से पांच हजार लीटर पानी की दरकार होती है। सीआरआरआई के क्रॉप प्रॉडक्शन डिवीजन के प्रमुख के. एस. राव कहते हैं कि धान की खेती में ऐसे अपव्ययी तरीके से पानी का इस्तेमाल टिकाऊ नहीं होता है।

आईआरआरआई के मुताबिक, धान की खेती में पानी का इस्तेमाल अगर वैश्विक स्तर पर 10 फीसदी कम कर दिया जाए तो गैर-कृषि की जरूरतों के लिए 150 अरब क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध हो सकता है। हालांकि एरोबिक राइस कल्टिवेशन में कुछ निश्चित तकनीकी समस्याएं हैं जिनसे उबरने के लिए खास कदमों की दरकार है। ऐसी ही एक समस्या है बिना खेतों में भरपूर पानी पहुंचाए बोआई करने के बाद प्रचुरता से उग आए खरपतवार। ये खरपतवार वहां मौजूद पोषक तत्त्व का उपभोग करने में फसलों से होड़ लेते हैं और इस तरह से फसलों को पर्याप्त पोषण से वंचित कर देते हैं। फसलों के विकास के शुरुआती 30 दिन की अवधि में यह समस्या खास तौर पर ज्यादा गंभीर होती है। सीआरआरआई वैज्ञानिकों ने खरपतवार के नाश के लिए रसायन इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। दूसरी मुख्य समस्या लौह की कमी की है। जब वहां स्थिर पानी नहीं होता है तो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन मिट्टी में उपलब्ध लौह का ऑक्सीजनीकरण कर देती है जिससे लौह पौधों के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। यह फसलों की उत्पादकता में कमी ला देता है। इससे निपटने के लिए विशेषज्ञ मिट्टी में आयरन सल्फेट मिलाने की सलाह देते हैं। एरोबिक राइस कल्टिवेशन की बाबत किए गए प्रयोग से जाहिर हुआ है कि बेहतर परिणाम तभी सामने आता है जब लेजर लैंड लेवलिंग मशीन के जरिए खेत को जोता और समतल किया जाता है। इसके साथ ही सीड ड्रिल मशीन की मदद से बीज बोने की दरकार होती है। पर्याप्त दूरी और गहराई के साथ-साथ एक सीध में बीज बोने के लिए मशीन पहले ही विकसित किए जा चुकेहैं। इसे बैल, ट्रैक्टर या पावर ट्रिल के जरिए संचालित किया जा सकता है। बीज बोने में मशीन के इस्तेमाल से कई फायदे मिलते हैं, जिनमें बीजों की बचत, प्रति हेक्टेयर ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाना, खरपतवार में कम से कम लागत और बेहतर उत्पादन शामिल हैं।

कम बारिश या सिंचाई के लिए अपर्याप्त जल की उपलब्धता से पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से बचाने में एरोबिक राइस कल्टिवेशन काफी सहायक हो सकता है। यह वैसे इलाकों के लिए भी खासा उपयोगी हो सकता है जहां भूमिगत जल में एक साथ कई फसलें उगाई जाती है मसलन पंजाब के उत्तरी पश्चिमी इलाके, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही दक्षिण के कुछ इलाके। अन्यथा ज्यादा दोहन के चलते गिर रहे भूजल स्तर को बचाने के लिए उन इलाकों में धान की खेती त्याग दी जानी चाहिए।

टैंसो मीटर से धान की खेती में पानी की बचत

पंजाब एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी ने एक ऐसा ही मीटर तैयार कर लिया है जो किसानों को बताएगा कि खेत को कब कितना पानी चाहिए। यह मीटर है टैंसो मीटर, जो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी महज 300 रुपये में किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मीटर के उपयोग से किसान 25 से 30 फीसदी तक पानी की बचत कर सकते हैं। यूनीवर्सिटी के मिट्टी व भू विभाग के प्रमुख डॉ. अजमेर सिंह सिद्धू के मुताबिक टेंसो मीटर एक छोटा सा पाइपनुमा मीटर है। इसे 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन में गाड़ दिया जाता है। पाइप के एक सिर पर पोरस कप नाम का उपकरण लगाया जाता है। पाइप पर हरे व पीले रंग की पट्टी हैं। पानी का स्तर जब दोनों पट्टियों के बीच में होता है तो किसान को यह संकेत मिल जाता है कि खेत में पानी की कमी है। उसे बेवजह पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

धान उत्पादक राज्यों में किसानों को अच्छी फसल उगाने के लिए खेत में पर्याप्त पानी भरा रखना जरूरी होता है। जबकि पानी की कमी के कारण इसमें मुश्किलें आ रही हैं। धान उगाने के लिए सिंचाई के पानी पर किसानों को काफी खर्च करना पड़ता है। आवश्यकता से ज्यादा पानी खेत में होने से न सिर्फ किसानों की लागत बढ़ जाती है बल्कि पानी का बर्बादी भी होती है। पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई के लिए जमीन से पानी का अत्यधिक दोहन होने के लिए भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। यह समस्या सरकार के सामने भी आ रही है। ऐसे में पानी के किफायती इस्तेमाल की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही उपकरण बनाया है जिससे धान के खेत में पर्याप्त पानी होने की जानकारी किसानों को मिल जाएगी। इससे पानी का सही उपयोग हो सकेगा और किसानों की सिंचाई लागत भी घटेगी। धान की रोपाई का सीजन शुरू हो चुका है। किसानों ने रोपाई के लिए खेत तैयार करने के मकसद से सिंचाई शुरू कर दिए हैं। इस साल बारिश में देरी हो रही है। ऐसे में नहरी पानी उपलब्ध न होने पर जमीन से पानी निकालना किसानों के लिए एकमात्र साधन रह गया है। ऐसे किसानों ने अपने ट्यूबवैलों से सिंचाई शुरू कर दी है। किसान अपने खेतों में तब तक सिंचाई करते रहेंगे जब तक उन्हें खेत में पर्याप्त पानी होने का भरोसा न हो जाए। लेकिन कई बार अनजाने में किसान जरूरत से ज्यादा पानी खेत में भर देते हैं।

स्थिति यह है कि इससे जमीन के पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इसके कारण पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। सिंचाई के लिए कब कितने पानी की जरूरत है, अब यह तकनीकी ढंग से किसानों को पता चल जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी ने एक ऐसा ही मीटर तैयार कर लिया है जो किसानों को बताएगा कि खेत को कब कितना पानी चाहिए। यह मीटर है टैंसो मीटर, जो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी महज 300 रुपये में किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मीटर के उपयोग से किसान 25 से 30 फीसदी तक पानी की बचत कर सकते हैं। यूनीवर्सिटी के मिट्टी व भू विभाग के प्रमुख डॉ. अजमेर सिंह सिद्धू के मुताबिक टेंसो मीटर एक छोटा सा पाइपनुमा मीटर है। इसे 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन में गाड़ दिया जाता है। पाइप के एक सिर पर पोरस कप नाम का उपकरण लगाया जाता है। पाइप पर हरे व पीले रंग की पट्टी हैं। पानी का स्तर जब दोनों पट्टियों के बीच में होता है तो किसान को यह संकेत मिल जाता है कि खेत में पानी की कमी है। उसे बेवजह पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यह उपकरण तभी प्रभावी होगा, जब इसे लगाने से करीब पंद्रह दिन पहले खेत में पानी भरा जाए।

डॉ. सिद्धू के मुताबिक इस यंत्र की बाजार में कीमत करीब 3000 रुपये है जबकि यूनीवर्सिटी इसे सीधे किसानों तक महज 300 रुपये में दे रही है। राज्य में जिस तरह धान से पानी का स्तर नीचे गिर रहा है उसे रोकने के लिए यह उपकरण काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस उपकरण के बार में किसानों को पूरी जानकारी भी दी जा रही है। डॉ. सिद्धू के मुताबिक कई बार ऐसी जमीन रहती है जहां पर पानी का ठहराव कम हो पाता है। ऐसे में किसानों को लगातार पानी देते रहना पड़ेगा। इस यंत्र के बिना किसान कई बार लापरवाही में आवश्यक सिंचाई नहीं करते हैं या फिर कई बार खेतों में पानी इतना ज्यादा दे देते हैं कि वह फसल को फायदा पहुंचाने की बजाए नुकसान पहुंचाने लगता है। यूनीवर्सिटी ने किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए टैंसो मीटर जैसा उपकरण तैयार किया है।

यूनीवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. जी.एस मांगट के मुताबिक धान की फसल के लिए प्रति एकड़ करीब 10 हजार क्यूबिक मीटर पानी का उपयोग हो रहा है। किसान औसतन धान के सीजन में 15 बार सिंचाई करते हैं। किसानों को तकनीकी रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं रहती है कि उन्हें सिंचाई के लिए कब कितना पानी उपयोग करना चाहिए। पानी का ज्यादा उपयोग भी फसल के लिए नुकसानदायक ही रहता है।

इसलिए किसानों को टैंसो मीटर जैसे उपकरण का उपयोग करना चाहिए ताकि गिरते भूजल को बचाया जा सके। पंजाब में हर साल डेढ से दो फीट तक पानी का स्तर नीचे गिर रहा है। जिसका नतीजा यह है कि बड़ी संख्या में किसानों को अपने ट्यूबवैल भी ज्यादा गहरे करवाने पड़ रहे हैं। जिन पर भारी भरकम खर्च आ रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

विश्वव्यापी कोरोना वायरस महामारी कोविड-१९ के संक्रमण की राज्य में रोकथाम तथा उसके उपचार

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में लिया अहम निर्णय

क्रांति समय दैनिक

अहमदाबाद,विश्वव्यापी कोरोना वायरस महामारी कोविड-१९ के संक्रमण की राज्य में रोकथाम तथा उसके उपचार के लिए अद्यतन उपकरण व मशीने खरीदने के लिए अब राज्य के विधायकों को अपनी ग्रांट में से कम से कम ५० लाख रुपए अनिवार्य रूप से आवंटित करने होंगे। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में गुरुवार को गांधीनगर में हुई कोर कमेटी की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य में नोवेल कोरोना वायरस-कोविड-१९ के संक्रमण के नियंत्रण तथा उपचार के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को ज्यादा गहन और व्यापक बनाने के लिए जनहितकारी स्वास्थ्य उन्मुख दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्णय किया है कि इस मकसद के लिए विधायक आवश्यकता के अनुसार अपनी पूरी विधायक ग्रांट का उपयोग भी कर सकते हैं।

विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य के जनप्रतिनिधियों को ग्रांट की इस रकम में से सिविल हॉस्पिटल या अन्य सरकारी हॉस्पिटल या क्लीनिक तथा महानगर पालिका एवं नगर पालिका की ओर से संचालित हॉस्पिटल या क्लीनिक में कोरोना के मौजूदा हालात में उसकी रोकथाम एवं उपचार के अद्यतन उपकरण व मशीनें खरीदने के लिए कम से कम ५० लाख रुपए अनिवार्य रूप से आवंटित करने होंगे।

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार पहले जहां विधायक अपनी इस ग्रांट का इस्तेमाल अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के उपकरणों की खरीदी के लिए करते थे,

वहीं अब वर्तमान कोविड-१९ की स्थिति में वे अपने जिले के सिविल हॉस्पिटल, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र या उप जिला हॉस्पिटल के लिए भी ग्रांट का उपयोग कर सकेंगे। इतना ही नहीं, चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित ऐसे हॉस्पिटल जो सेवाभाव से 'न लाभ, न हानि' के आधार पर चलते हैं, वैसे हॉस्पिटलों के लिए भी कोविड-१९ की स्थिति में ५० लाख रुपए की सीमा में ट्रस्ट के योगदान के बिना विधायक की ग्रांट से अद्यतन उपकरण या सामग्री की खरीदी हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने यह उदार दृष्टिकोण भी अपनाया है कि सरकारी या स्थानीय निकाय की ओर से संचालित हॉस्पिटल-दवाखानों की जरूरतों तो ध्यान में रखते हुए इस जरूरत के अनुसार विधायक ग्रांट से आवंटित की जाने वाली रकम के लिए कोई सीमा लागू नहीं होगी।

विधायकों की कम से कम ५० लाख रुपए की इस ग्रांट से जिन उपकरणों या सामग्री की कोविड-१९ संक्रमण के नियंत्रण और उपचार के लिए खरीदी की जा सकेगी,

उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर-१० लीटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइस, बाइपैप मशीन, मल्टी पैरा मॉनिटर, सिरिंज इंफ्यूजन पंप (१०, २०, ५० एमएल), लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक (६००० लीटर) और प्रेशर स्विंग अबसॉर्प्शन(पीएसए) ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट (२५० और ५०० लीटर) का समावेश होता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि विधायक ग्रांट के ये प्रावधान कोविड-१९ की विशिष्ट परिस्थिति में केवल वर्ष २०२१-२२ के लिए मंजूर किए जाने वाले कार्यों पर ही लागू होंगे। इसके अलावा, ऐसे कार्यों के क्रियान्वयन-खरीदी के लिए नियत अमलीकरण कार्यालयों को उनके संबंधित विभाग के वर्तमान नीति-नियमों का पालन करना होगा।

विधायक निधि से कार्यों को मंजूर कर उसके कार्यान्वयन के मामले में राज्य सरकार के अन्य वर्तमान प्रावधान यथावत रखे गए हैं।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत

उच्च शिक्षा संस्थानों में एन.सी.सी. एक इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के अंतर्गत संरेखित हेतु कर्नल शर्मा ने ली कुलपति की मुलाकात.

क्रांति समय संवाददाता

सूरत :एन.सी.सी. बटालियन के कर्नल एस.जे. शर्मा इन्होने सूरत शहरमें आई वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. किशोरसिंह चावड़ा इनसे मुलाकात ली थी। उन्होंने बताया की शिक्षा का मानव जीवन में काफी सारा योगदान होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० (ह्रश्वक्क-२०२०) ने पाठ्येतर, सह पाठयक्रम और पाठयक्रम गतिविधियों के बीच कठिन अलगाव को दूर करने और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के तहत क्रेडिट पाठ्यक्रम जैसी सभी गतिविधियों की पेशकश करने का प्रस्ताव दिया है। इसलिए, एनसीसी को पाठयेतर गतिविधि से पाठयक्रम गतिविधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और अधिमानत एक विषय के रूप में या सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाना चाहिए, जिसमें समुदाय आधारित जुड़ाव और सेवा के क्षेत्रों में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएं शामिल हैं। पहले चरण में २४ क्रेडिट स्कोर के 'जेनेरिक इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स' के रूप में एनसीसी केवल उन कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिन के पास पहले से ही एनसीसी उप-इकाइयाँ है और केवल उन्हीं छात्रों को विस्तारित किया जाता है जो एनसीसी कैडेट के रूप में नामांकित हैं। दूसरे चरण में, वड़ोदरा, नर्मदा, छोटाउदेपुर, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, यूटी दादरा और नगर हवेली और दमन के जिलों में किसी भी केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्वायत्त कॉलेजों को एन.सी.सी. की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी। एक क्रेडिट कोर्स, उन शैक्षिक संस्थानों के अधीन है जो संकाय के कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं, प्रशिक्षित कर्मचारियों को काम पर रखते हैं और पूरी तरह से स्व-वित्त योजना (एफ.एस.एफ.एस.) और मुख्यालय की मंजूरी द्वारा शासित आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करते है।

हमारे पत्रकार श्री आदेश साबळे इनसे बात करते हुवे कर्नल शर्मा और कुलपति इन्होने बताया की सीबीसीएस के तहत च्सामान्य ऐच्छिक क्रेडिट कोर्सज्ज के रूप में एनसीसी विभिन्न प्रमुख लाभ है। जैसे की एनसीसी कैडेट के रूप में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को मूल्यवान एनसीसी 'बी' और 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अलावा एनसीसी प्रशिक्षण के लिए अकादमिक ऋण प्राप्त करने से काफी लाभ होगा। एनसीसी प्रशिक्षण पर अपने काम के भार के लिए एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों को देयऋण के अलावा अतिरिक्तजवाब देही और छात्रों की अपेक्षा के आधार पर एनसीसी प्रशिक्षण मानकों को मजबूत करना। कैडेट के रूप में अधिक छात्र विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत एनसीसी कैडेटों को रोजगार प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

अधिक बात करते हुए उन्होंने कहा, एन.सी.सी. में बचपन में राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति एकता और अनुशासन संबंधी प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक युवा इस देश में अपना अमूल्य योगदान देता रहे।

सार-समाचार

म्युकोरमाइकोसिस के केस २०० के पार, सिविल अस्पताल में ३० बेड का नया वोर्ड शुरु

राजकोट,शहर में कोरोना के बाद म्युकोरमाइकोसिस का खतरा मंडरा रहा है। शहर में म्युकरमाइकोसिस के केस २०० के पार पहुंच चुके है। सिविल अस्पताल में म्युकरमाइकोसिस बिमारी से पीडित मरिजों के लिए ३० बेड का नया वोर्ड शुरुकिया है।

राजकोट में कोरोना के बाद म्युकोरमाइकोसिस की जानलेवा बिमारी फैलने से लोगों में दहशत फैल गई है। कोरोनाग्रस्त मरिज अब म्युकरमाइकोसिस नामक फूग प्रकार की बिमारी का शिकार हो रहे हैं। पिछले १५ दिनों में इस बिमारी से अनेक लोगों की मौत हो गई। शहर में हाल म्युकरमाइकोसिस के केस २०० के पार पहुंच चुके है। जिसके लिए सिविल अस्पताल में ३० बेड का अलग वोर्ड शुरुकिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद इस म्युकरमाइकोसिस के बिमारी में कारगत इंजेक्शन की किल्लत हो रही है। सिविल सुप्रिटेन्डेन्ट ने दावा किया है कि इस बिमारी के लिए इंजेक्शन एन्फोटेरिसीन-बी ५०, लीपोसोमाल एन्फोटेरिसीन ५० मिलीग्राम इंजेक्शन सिविल अस्पताल में पर्याप्त है। इंजेक्शन व दवाइयां पर्याप्त मात्रा में है। परंतु मेडिकल स्टोर में यह इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। इस बिमारी से पीडित मरिजों व उनके परिजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

कोरोना संक्रमित मरिजों को स्टीरोइड देने से रोगप्रतिरोधक शक्तिमें कमी होने से म्युकरमाइकोसीस का इन्फेक्शन फैल रहा है। डायाबिटीस, केन्सर और शरीर में किसी भी प्रकार की सर्जरी, स्कीन के रोग के मरिजों को म्युकरमाइकोसीस का जोखिम अधिक हो रहा है। इस बिमारी की शुरुआत नाक व गले से होती है। फंगस नाक में भर जाने पर सांस लेने में दिक्कत होती है। फंगस, आंख, फेफडे व सिर तक पहुंच जाती है। यह एक प्रकार की फूग ही है। हाल म्युकरमाइकोसिस इंजेक्शन अहमदाबाद से राजकोट भेजा गया है। कोरोना के मरिजों को स्टीरोइड का इंजेक्शन दिया जाता है जिसके बाद म्युकोरमाइकोसिस बढ रहा है। वहीं दूसरी ओर इस बिमारी से ठीक होने के बाद लंबा इलाज जारी रहता है। इस बिमारी का खतरा डायाबिटीज के मरिजों को अधिक रहता है जिसमें कई केस में मरिज की मौत की भी संभावना बढ जाती है। डॉक्टरों की भी सबसे बडी परेशानी यह है कि म्युकरमाइकोसिस को खत्म करने के लिए दिए जानेवाले इंजेक्शन किडनी को क्षति पहुंचा रहा है।

सार समाचार

लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कर्नाटक में लॉकडाउन लगना निश्चित है : येदियुरप्पा

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कोरोना वायरस के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ने के मद्देनजर शुक्रवार शाम की अहम बैठक से पहले यहां अनम्मा देवी मंदिर के पास संवाददाताओं से कहा, 'लोग सही तरीके से जनता कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं। वे हमारी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए, लॉकडाउन लगाना जरूरी हो सकता है।' येदियुरप्पा के मुताबिक, सरकार कोविड को नियंत्रित करने के लिए एक या दो दिन में सख्त उपायों के बारे में अंतिम फैसला करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, 'अगर लोग चाहते हैं कि सख्त कदम न उठाएं जाएं तो उन्हें मास्क पहनकर और शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सहयोग करना होगा।' उन्होंने कहा कि अन्यथा, सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो जाएगा। ऑक्सीजन संकट के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह ईमानदारी से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में बिस्तर दिलाने के अनुरोध के साथ कोविड मरीजों और उनके रिश्तेदारों का मुख्यमंत्री आवास और विधान सौध आने से जुड़े सवाल पर येदियुरप्पा ने कहा कि यह अनुचित है और लोगों को यह रोकना होगा। उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगा कि अपना दुख बताना गलत है। मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं और मैं लोगों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों के लिए काम करते हैं।

राजस्थान सरकार ने रूस से खरीदे ऑक्सीजन सांद्रक, पहली खेप जल्द ही राज्य में पहुंचेगी

जयपुर। कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए सभी जरूरी उपकरण जुटाने की कोशिश कर रही राजस्थान सरकार ने रूस से ऑक्सीजन सांद्रक (कंसंट्रेटर)मंगवाए हैं। इसके अलावा वह चीन से भी ऑक्सीजन सांद्रक खरीद रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि रूस से 100 ऑक्सीजन सांद्रक की पहली खेप आज यहां पहुंचेगी। प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए विदेशों से ऑक्सीजन सांद्रक मंगवाने के निर्देश दिए थे,इसके तहत 100 ऑक्सीजन सांद्रक की पहली खेप आज शाम यहां पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि सरकार चीन से भी इस तरह के सांद्रक मंगवा रही है। प्रवक्ता के मुताबिक राजस्थान सरकार ने विभिन्न स्रोतों से ऑक्सीजन सांद्रक सहित अन्य जरूरी चिकित्सा उपकरण खरीदने की संभावना तलाशने के लिए पिछले दिनों एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया था जिसमें आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल, प्रीतम बी यशवंत व टीना डाबी शामिल हैं। यह समूह विदेशों से इस तरह की सामग्री खरीदने का प्रयास कर रहा है।

चिदंबरम का आरोप, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा

नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को देश में कोरोना महामारी की स्थिति के 'बद से बदतर' होने का दावा किया और आरोप लगाया कि इस हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, ''महामारी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। टीकों की अपर्याप्त आपूर्ति एक जटिल, कड़वा सच है, लेकिन सरकार अब भी इनकार कर रही है। तमिलनाडु में, 45 साल के अधिक उम्र वाले सभीलोगों को पहली खुराक नहीं मिल रही है, और दूसरी खुराक लेने वालों की संख्या बहुत छोटी है।'' पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, ''18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों के बीच के किसी को भी टीका नहीं लग रहा है। अन्य राज्यों में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है।'' चिदंबरम आरोप लगाया, ''प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का मजाक उड़ा रहे हैं।'' देश में एक दिन में कोविड-19 के 4,14,188 नये मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को संक्रमण के कुल मामले 2,14,91,598 हो गए, जबकि 3,915 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 2,34,083 हो गई।

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा राजनीति का 'रक्तरंजित' रूप है : शिवसेना

मुंबई। शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हिंसा से राजनीति का 'रक्तरंजित' रूप उजागर हुआ है और यह दिखाता है कि लोकतंत्र के बजाए ताकत तथा बाहुबल का शासन कायम है। पार्टी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार दोनों पर समान रूप से है। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में कहा है, ''पश्चिम बंगाल में वास्तव में क्या हो रहा है और इसके पीछे किसके अदृश्य हाथ हैं? ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जबसे राज्य में भाजपा हारी है हिंसा की खबरें आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं से मारपीट की। लेकिन यह सब दुष्प्रचार है।' 'सामना' में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में मारे गए 17 लोगों में नौ भाजपा से जुड़े लोग थे, बाकी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष इसमें संलिप्त हैं। संपादकीय में कहा गया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात कर हालात की जानकारी ली।

मोदी सरकार ने जनता को निराशा किया, कोरोना के हालात को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए : सोनिया

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने और जनता को निराश करने का आरोप लगाया और आग्रह किया कि मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए हुई कांग्रेस सांसदों की डिजिटल बैठक में सोनिया ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक बुलाई जाए ताकि महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए कदम उठाना और जवाबदेही तय करना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, ''देश एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर रहा है। हजारों लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह देखना दुखद है कि लोग अस्पतालों में और सड़कों पर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तथा किसी भी तरह चिकित्सा सुविधा चाहते हैं।'' उन्होंने सवाल किया, '' मोदी सरकार क्या कर रही है? लोगों की पीड़ा और दर्द को कम करने की बजाय उसने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से पल्ला झाड़ लिया है।''

सोनिया के मुताबिक, सरकार के खुद के विशेषाधिकार समूह और राष्ट्रीय कार्य बल ने मोदी सरकार को आगाह किया था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी और इसके लिए तैयारी करने का भी आग्रह किया था। उन्होंने कहा, ''स्वास्थ्य संबंधी संसद की स्थायी समिति और विपक्षी दलों ने हमारी तैयारियों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने इस साल अंहकार के साथ ऐलान कर दिया कि उन्होंने कोरोना महामारी पर जीत हासिल कर ली है तथा उनकी पार्टी ने इस तथाकथित सफलता के लिए उन्हें सम्मानित भी किया।'' सोनिया ने दावा किया, ''विशेषज्ञ की सलाह की उपेक्षा करते हुए मोदी सरकार ने ऑक्सीजन, दवाओं और वेंटिलेंटर की आपूर्ति को मजबूत नहीं किया। हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार टीकों का समय पर ऑर्डर देने में विफल रही। इसके साथ ही, वह उन परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये आवंटित करती रही जिसका जनता के कल्याण से कोई लेना-देना नहीं है।'' उन्होंने कांग्रेस सांसदों से कहा, ''आपको पता है कि संसद ने कोरोना के मुफ्त टीकाकरण के लिए 35000 रुपये का प्रावधान किया, लेकिन मोदी सरकार इसका बोझ भी राज्य सरकारों पर पर डाल रही है। उसने टीकों की अलग अलग कीमत को मंजूर दी है तथा टीकों का निर्माण बढ़ाने के लिए जरूरी लाइसेंस भी नहीं दिए।'' कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ''मोदी सरकार की गैरबराबरी वाली टीकाकरण नीति के कारण करोड़ों दलित, आदिवासी, ओबीसी, गरीब और कमजोर लोग टीके से उपेक्षित रह जाएंगे। यह हैरान करने वाली बात है कि मोदी सरकार लोगों के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता और कर्तव्यों को छोड़ दिया है।''

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ''यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि व्यवस्था विफल नहीं हुई है। मोदी सरकार भारत की कई क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करने में अक्षम रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि आज भारत को उस राजनीतिक नेतृत्व ने निर्बल बना दिया है जिसे जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मोदी सरकार ने हमारे देश के लोगों को निराश किया है।'' उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और खुद की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्रों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने विपक्ष के सुझावों को अनसुना कर दिया। सोनिया ने कहा, ''कोविड का संकट 'सरकार बनाम हम' की लड़ाई नहीं है, 'बल्कि हम बनाम कोरोना' है। हम एक राष्ट्र के तौर पर इस लड़ाई को लड़ना होगा। मेरा मानना है कि मोदी सरकार को कोविड के हालात को लेकर तत्काल सर्वदलीय बैठक

बुलानी चाहिए।'' सोनिया ने कहा, ''कांग्रेस की यह मांग भी है कि संसद की स्थायी समिति की बैठक भी बुलाई जाए ताकि महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने संकट की इस घड़ी में लोगों की सहायता करने के लिए पार्टी और उसके विभिन्न संगठनों खासकर युवा कांग्रेस की तारीफ भी की।

कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के बीच लोगों की परेशानियां दूर करने में जुटे हैं रक्षा संगठन : राजनाथ

नई दिल्ली(एजेंसी)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और राष्ट्रीय कैडेट कोर जैसे संगठन देश में कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर लोगों को पेश आने वाली परेशानियों को दूर करने में जुटे हैं। सिंह ने अपने वेबसाइट पर ब्लाग पोस्ट में कोविड से मुकाबला करने से संबंधित नयी सुविधाएं स्थापित करने, स्वास्थ्य पेशेवरों की तैनाती जैसे कार्यो का जिक्र किया जो रक्षा मंत्रालय से जुड़े संगठनों द्वारा किये गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है और कई राज्यों में अस्पतालों में आक्सीजन तथा दवा, उपकरणों, बिस्तरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

राजनाथ सिंह ने बताया कि सेना, नौसेना और वायु सेना किस तरह से देशवासियों की जान बचाने में लगी हुई हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री के पोस्ट पर ट्वीट करते हुए कहा कि 'जल, थल और नभ'....हमारे सशस्त्र बल कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी ओर, रक्षा मंत्री ने अपने पोस्ट में बताया कि इस वायरस से निपटने के लिए सेना को आपात वित्तीय शक्तियां दी गई है ताकि कमांडरों को पृथकवास केंद्र से लेकर अस्पताल बनाने तक कोई

भी सामान खरीदने के लिए असुविधा का सामना ना करना पड़े। सिंह ने बताया कि डीआरडीओ, कैंटॉनमेंट बोर्ड, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा जैसे विभिन्न रक्षा संगठनों ने कोविड अस्पताल स्थापित किये हैं। जरूरत के हिसाब से बड़े शहरों में सशस्त्र बलों से जुड़े अस्पतालों की व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु और पटना से शुरूआत की गई है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर और जगह भी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की तरफ से कई अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और अर्द्ध स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। इस संस्था में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर काम कर रहे 238 डॉक्टरों को 31 दिसंबर 2021 तक सेवा विस्तार दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि सेना ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और लखनऊ में 100. 100 बिस्तर तैयार किए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सागर में भी सेना ने 40 बिस्तर का पृथकवास केंद्र शुरू किया है। सिंह ने बताया कि इसके अलावा भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर तथा झारखंड के नामकुम में भी पृथकवास केंद्र स्थापित किये गए हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि वायु मार्ग से जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी वायु सेना ने ली हुई है। देश ही नहीं विदेशों से ऑक्सीजन लाने का काम भी वायुसेना कर रही है। वायुसेना ऑक्सीजन कंटेनर भी विदेशों से ला चुकी है। उन्होंने बताया कि नौसेना ने अपनी कई जहाजों को ऑक्सीजन पहुंचाने में लगाया गया हैं। नौसेना ने ऑक्सीजन की पहली खेप आईएनएस तलवार के जरिए बहरीन से कर्नाटक के मंगलौर पहुंचायी गई थी। इसके अलावा नौसेना के आईएनएस जलाश्व और आईएनएस ऐरावत के जरिए कोलकाता और कोच्चि में ऑक्सीजन टेंक भेजे गए। सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने दिल्ली और लखनऊ में 500 बिस्तर और अहमदाबाद में 900 बिस्तर का कोविड देखरेख सेंटर स्थापित किया है। इतना ही नहीं पटना में ईएसआईसी के अस्पताल को कोविड सेंटर में तब्दील कर 500 बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 120 संयंत्रों का संचालन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की मदद से किया जा रहा है। 2 संयंत्र दिल्ली के एम्स और आरएमएल अस्पताल में लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ पीएम केयर्स फंड से प्राप्त आवंटन से 500 चिकित्सा आक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का काम कर रहा है।

हेमंत सोरेन ने की प्रधानमंत्री की आलोचना, भाजपा नेताओं ने किया पलटवार

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की आलोचना के लिए भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि उन्होंने संवैधानिक पद की गरिमा को धूमिल किया। दरअसल, प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को फोन पर सोरेन से बात की थी और झारखंड में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया था, ''आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते।'' झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने ट्वीट किया, ''कुछ नेता इस स्तर तक गिर गए हैं। प्रधानमंत्री फोन करते हैं और कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करते हैं। कम से कम अपने पद की गरिमा का तो ख्याल रखना चाहिए।''भाजपा सांसद और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी ने भी हेमंत सोरेन की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया, ''ना आपको देश के संघीय ढांचे का ज्ञान, नसामान्य शिष्टाचार की समझ, न बड़ों से व्यवहार का प्रशिक्षण और न ही अपनी कुनीतियों से बेहाल झारखंड की चिंता है हेमंत सोरेन। जनता आपकी गलत नीतियों की भेंट न चढ़े। आप झारखंड के लोगों को उनके हाल पर छोड़ सकते हो मगर मोदी सरकार हर क्षण उनके साथ है।'' असम भाजपा के नेता हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि सोरेन का ट्वीट सामान्य शिष्टाचार के खिलाफ है और लोगों की परेशानियों का मजाक उड़ाने जैसा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनका हाल चाल के लिए फोन किया था। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने पद की गरिमा को धूमिल किया है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओड़िशा के साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री को फोन कर कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया था। झारखंड सरकार के सूत्रों का कहना है कि सोरेन इस बात से दुखी थे कि वह राज्य की पीड़ा प्रधानमंत्री के समक्ष नहीं रख सके और प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी बात की।

दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने रोहिणी, खान मार्किट में मारे छापे

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

दिल्ली के खान मार्किट में एक रेस्तरां के प्रबंधक सहित चार आदमियों को कथित तौर पर जमाखोरी करने और ऑक्सीजन स्टोर करके काला बाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को नई दिल्ली के खान मार्केट इलाके में एक रेस्तरां से नौ और ऑक्सीजन सांद्रता बरामद की। लोधी कॉलोनी के केंद्रीय बाजार में नेगे जू रेस्तरां और बार में छापेमारी करने के बाद गुरुवार को पुलिस ने 419 ऑक्सीजन सांद्रता बरामद की है। अतुल ठाकुर, डीसीपी (दक्षिण) ने कहा कि फॉलोअप छापे में उन्होंने आरोपी हितेश के इशारे पर खान मार्केट में टाउन हॉल रेस्तरां से नौ और अधिक सांद्रता बरामद की हैं, जिन्हें गुरुवार को लोधी कॉलोनी में एक रेस्तरां में छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि गुरुवार को

छापेमारी के दौरान लैपटॉप में बरामद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के चालान मिले। अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के स्टिकर जो प्रति सांद्रता 69,999 की कीमतों को दर्शाते हैं, भी बरामद किए गए। पुलिस ने कहा एक विस्तृत जांच की जा रही है और इस कालाबाजारी रैकेट के पीछे अधिक सांद्रता वाले और अन्य अपराधियों और ऑक्सीजन बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों रेस्तरां एक व्यापारी नवनीत कालरा के हैं, जो दिल्ली-एनसीआर में कई रेस्तरां के मालिक हैं। अधिकारी ने कहा, 'मामले की जांच चल रही है और हम मामले में मालिक की भूमिका का पता लगा रहे हैं। यदि आवश्यक हुआ तो उसे जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा।' इसके अलावा रोहिणी निवासी प्रहलाद कुमार को ष्ट्टह्ङ्कढ्ढष्ठ19 ड्रग रेमेडिसविर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से तीन इंजेक्शन बरामद किए। नांगलोई पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420/188 और 3 महामारी रोग अधिनियम 1987 के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्तमान कोविड19 स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे।

पश्चिम बंगाल में बढ़े कोरोना संक्रमित मरीज, ममता ने मोदी सरकार से मांगी ऑक्सीजन की मदद

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा केंद्र ने पश्चिम बंगाल की बढ़ी हुई जरूरतों के बावजूद राज्य में उत्पादित ऑक्सीजन में से अन्य राज्यों का आवंटन बढ़ा दिया।

ममता ने पीएम को लिखा पत्र?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि कोविड मामलों में उछाल के साथ, बंगाल की ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ रही है और ऐसे समय में, केंद्र अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति अन्य राज्यों में कर रहा है।

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कहा है कि पिछले एक सप्ताह में बंगाल में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 470 मीट्रिक टन से बढ़कर 550 मीट्रिक टन हो गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार पहले ही केंद्र के साथ इस मामले को उठा चुकी है कि राज्य को अब दैनिक आधार पर 550 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता है।

केंद्र ने क्या किया?

पश्चिम बंगाल की आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार ने आवंटन के बजाय, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में कुल उत्पादन से अन्य राज्यों के लिए एमओ का आवंटन बढ़ा दिया है, पिछले 10 दिनों के दौरान 230 मीट्रिक टन से 360 मीट्रिक टन, रखते हुए ममता बनर्जी ने अपने पत्र में पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए प्रति दिन 308 मीट्रिक टन की आवश्यकता के बावजूद, प्रतिदिन 550 मीट्रिक टन की आवश्यकता है।

तमिलनाडु में अजब संयोग, स्टालिन को रिपोर्ट करेंगे गांधी और नेहरू

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

एक केंद्र शासित प्रदेश सहित पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। असम, पश्चिम बंगाल और केरल में जहां सत्ता बरकरार रही तो वही पुडुचेरी और तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुए। तमिलनाडु में डीएमके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 133 सीटें हासिल की। उसके नेता एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई में 34 सदस्यों वाले नए कैबिनेट का भी ऐलान हुआ है। कैबिनेट में सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है कि इसमें स्टालिन के साथ गांधी और नेहरू भी होंगे। इसे संयोग कहें या फिर प्रयोग कहिए। लेकिन यह बात तो है ही कि तमिलनाडु के साथ-साथ उनके कैबिनेट में गांधी और नेहरू भी होंगे। गांधी और नेहरू दोनों स्टालिन को रिपोर्ट करेंगे। शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने स्टालिन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मंत्रियों की सूची पर भी मुहर लगा दी। एमके स्टालिन पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं।

कैबिनेट में शामिल केएन नेहरू को स्टालिन ने नगर पालिका परिषद प्रशासन का पद सौंपा है, वही आर गांधी को हथकरघा, खादी ग्राम उद्योग आदि का मंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर कहें तो तमिलनाडु में नगर विकास मंत्रालय नेहरू के पास होगा तो वही खादी और ग्रामीण रोजगार विभाग गांधी चलाएंगे। यह बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। केएन नेहरू डीएमके के पुराने और कद्दावर नेता हैं। 1989 में पहली बार चुनाव जीतने के बाद वह लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। उनके पिता ने जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित होकर उनका नामकरण किया था। बात गांधी की करें तो वह रानीपेट सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं। पहली बार 1996 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे।

विधानसभा चुनाव में द्रमुक को मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 68 वर्षीय स्टालिन को राजभवन में आयोजित सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। स्टालिन के बाद कुल 33 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई जिनमें से 15 पहली बार मंत्री पद संभालेंगे। स्टालिन समेत सभी 34 ने अपनी अंतरात्मा और द्रमुक की दशकों पुरानी परंपरा के अनुरूप तमिल में शपथ ली। शपथग्रहण से पहले, सफेद कमीज और धोती पहने स्टालिन ने पुरोहित को अपने मंत्रिमंडल का परिचय दिया। द्रमुक के दिग्गज नेता एवं महासचिव दुराईमुरुगन को स्टालिन के बाद शपथ दिलाई गई और उन्हें सिंचाई परियोजनाओं में जल संसाधन मंत्री का प्रभार दिया गया तथा उनके पास खान एवं खनिज विभाग रहेगा। इससे पूर्व 2006-11 में द्रमुक के शासन में उनके पास लोक निर्माण कार्य जैसे विभागों का प्रभार था। गृह एवं अन्य विभागों जैसे लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन, अखिल भारतीय सेवा, जिला राजस्व अधिकारी, विशेष कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभागों का प्रभार मुख्यमंत्री स्टालिन का पास होगा। पूर्व निवेश बैंकर, पलानीवेल त्यागराजन, वित्त एवं मानव संसाधन मंत्री होंगे। केकेएसएसआर रामचंद्रन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री होंगे। यहां के प्रख्यात पार्टी नेता और चेन्नई के पूर्व महापौर मा सुब्रमण्यन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होंगे।

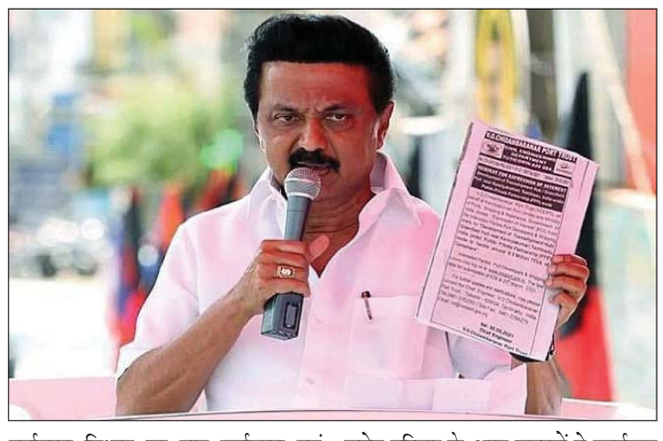

के पोनमुदी उच्च शिक्षा मंत्री, थंगम तनारासू उद्योग मंत्री और पी के सेकाराबू हिंदू धर्म एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग का मंत्री बनाया गया है। वी सेंथिल बालाजी को बिजली विभाग का प्रभार दिया गया है। वह जे जयललिता की अगुवाई वाली अन्नाद्रमुक सरकार के दौरान 2011 से 2015 के बीच परिवहन मंत्री रहे थे और 2018 में द्रमुक में शामिल हो गए थे कृषि एवं पर्यावरण समेत कई विभागों का नाम बदल दिया गया है जैसे कृषि विभाग अब कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग है और

पर्यावरण विभाग का नाम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। एमआरके पनीरसेल्वम कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री होंगे। ई वी वेलु लोक निर्माण मंत्री होंगे। गैर निवासी तमिल कल्याण एक नया विभाग है जिसका प्रभार जिंगी के एस मस्तान के पास होगा। उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बनाया गया है। स्टालिन की पत्नी दुर्गा और त्रिपलीकेन-चेपॉक सीट से चुनाव जीते उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। द्रमुक अध्यक्ष के बड़े भाई एम के अलागिरि के बेटे दयानिधि एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन उपस्थित थे। मंत्रिमंडल में दो महिला मंत्री भी हैं - पूर्व मंत्री पी गीता जीवन जिन्हें समाज कल्याण एवं महिला सशक्तीकरण और एन कयालविजि सेल्वाराज जिन्हें आदि द्रविड़ार कल्याण मंत्री बनाया गया है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)